

मशोबरा डाकघर ज़िला शिमला हिमाचल प्रदेश के लिए प्रस्तावित भूमि अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन एवं सामाजिक प्रभाव आंकलन

हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित
प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार (सामाजिक प्रभाव आंकलन और
सहमति) नियम-2015 के तहत

अंतिम रिपोर्ट

द्वारा
प्लान फ़ाउंडेशन



प्रस्तुत

हि० प्र० सामाजिक समागत आकलन इकाई शिमला

तालिका सूची

1	विस्तृत परियोजना ब्यौरा	1
1.1	परियोजना की पृष्ठभूमि	1
1.1.1	अंतर राज्य / अंतर्राष्ट्रीय पहलू	2
1.1.2	विकासक की पृष्ठभूमि	2
1.1.3	शासन या प्रबंधन संरचना	3
1.2	परियोजना औचित्य और सार्वजनिक उद्देश्य	4
1.3	परियोजना विवरण	4
1.3.1	अवस्थिति	5
1.4	विकल्पों पर विचार	8
1.5	परियोजना निर्माण के चरण	8
1.6	मुख्य डिजाइन सुविधाएँ, आकार और सुविधाओं का प्रकार	8
1.7	सहायक अवसंरचनात्मक सुविधाओं की आवश्यकता	8
1.8	कार्यबल की आवश्यकता (अस्थायी और स्थायी)	8
1.9	एसआईए या ईआईए का विवरण और अन्य तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट।	8
1.10	लागू किये गए विधान और नीतियां	9
1.10.1	सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की तैयारी	9
2	दल संरचना, दृष्टिकोण, प्रणाली एवं सामाजिक समाघात निर्धारण की अनुसूची	10
2.1	दल विवरण	10
2.2	प्रयुक्त पद्धति और उपकरण का विवरण व औचित्य	11
2.2.1	लक्ष्य	11
2.2.2	उद्देश्य	11
2.2.3	पद्धति	12
2.2.4	पद्धति का औचित्य	13

2.3	सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए सूचना संग्रहण करने के लिए संसाधन.....	14
2.4	नमूनाकरण पद्धति.....	15
2.5	सूचना अथवा डाटा स्रोतों के प्रयोग का पर्यवलोकन.....	15
2.6	प्रमुख हितधारकों के साथ परामर्श और की गई लोक सुनवाई के संक्षिप्त विचरण की अनुसूची.....	16
3	भूमी निर्धारण.....	20
3.1	भूमि तालिका की सूचना और प्राथमिक स्रोतों से जानकारी.....	20
3.2	परियोजना के प्रभाव में, प्रभाव का संपूर्ण क्षेत्र	20
3.3	परियोजना के लिए कुल भूमि की आवश्यकता	20
3.4	क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में किसी भी सार्वजनिक, अनुपयोगी भूमि का वर्तमान उपयोग	21
3.5	परियोजना के लिए आवश्यक भूमि के उपयोग हेतु प्रस्तावित पहले से ही खरीदी गई भूमि, अलग - अलग, लीज़ /अर्जित और प्रत्येक भूखंड के लिए प्रस्तावित उपयोग.....	21
3.6	परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि की मात्रा और स्थान.....	21
3.7	भूमि का वर्तमान उपयोग प्रकृति, और वर्गीकरण	21
3.8	जोत / भूमी का आकार, स्वामित्व प्रकार.....	22
3.9	भूमि वितरण एवं अधिग्रहीत किये जा रहे आवासीय भवनों की संख्या	22
3.10	भूमि की कीमतें और हाल ही में स्वामित्व और हस्तांतरण में परिवर्तन.....	22
4	प्रभावित परिवारों और परिसंपत्तियों का प्राक्कलन और गणना	23
4.1	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्ति	23
4.1.1	किराएदार / कब्जाधारी.....	23
4.1.2	जनजाति और पारंपरिक वन निवासी	23
4.1.3	सामान्य संपत्ति संसाधनों पर निर्भरता.....	23
4.1.4	राज्य सरकार द्वारा दी गई भूमि.....	23
4.1.5	आजीविका के लिए भूमि पर निर्भरता	24
4.2	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित, उत्पादक संपत्तियों की सूची और महत्वपूर्ण भूमि	24
5	सामाजिक- आर्थिक और सांस्कृतिक प्रोफाइल	25

5.1	आय और गरीबी का स्तर	25
5.2	कमजोर समूह.....	26
5.3	भूमि उपयोग और आजीविका	26
5.4	नातेदारी पैटर्न	26
5.5	प्रशासनिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और नागरिक समाज संगठन	26
5.6	क्षेत्रीय गतिशीलता और ऐतिहासिक परिवर्तन प्रक्रियाएं	26
5.7	जीवंत पर्यावरण की गुणवत्ता.....	26
6	सामाजिक प्रभाव	28
6.1	प्रभावों की पहचान करने के लिए रूपरेखा और दृष्टिकोण.....	28
6.2	परियोजना के विभिन्न चरणों में प्रभावों का विवरण.....	28
7	अर्जन पर लागत और लाभ और सिफारिशों का विश्लेषण	30
7.1	लोक प्रयोजन का आकलन	30
7.2	न्यूनतम विस्थापन विकल्प और न्यूनतम भूमि की आवश्यकता.....	30
7.3	सामाजिक प्रभावों की प्रकृति और तीव्रता.....	31
7.3.1	अंतिम सिफारिश	31
8	सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना	33
8.1	शमन के लिए दृष्टिकोण	33
8.2	समाघात से बचाव, कम करने और प्रतिपूर्ति करने के उपाय.....	33
8.3	आर एंड आर में शामिल उपाय और अधिनियम 2013 के अनुरूप मुआवज़ा.....	33
8.3.1	एसआईएमपी कार्यान्वयन के लिए परिव्यय	35
8.4	आवश्यक निकाय द्वारा सुझाए गए उपाय	38
8.5	अपेक्षित निकाय द्वारा सुझाए गए अतिरिक्त उपाय.....	38
8.6	पुनर्वास और पुनर्वस्थापन योजना के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत व्यवस्था	38
9	निष्कर्ष और सिफारिश.....	39

10 संदर्भ 42

तालिका विवरण

तालिका 1-1: परियोजना का विवरण	5
तालिका 2-1: टीम विवरण	10
तालिका 2-2: सर्वेक्षकों की सूची	11
तालिका 2-3: सूचना और डेटा स्रोतों का अवलोकन	16
तालिका 2-4: मशोबरा, हिमाचल प्रदेश में मुख्य संलग्नकों के साथ निर्धारित सार्वजनिक परामर्श तिथि	16
तालिका 3-1: अधिग्रहण के तहत पीएएफ की भूमि	20
तालिका 3-2: अधिग्रहित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि और उसका अभीष्ट उपयोग	21
तालिका 3-3: प्रस्तावित भूमि का वर्गीकरण	21
तालिका 5-1: प्राथमिक हितधारकों का विवरण	25
तालिका 8-1: पहचाने गए और संबंधित शमन उपाय	34
तालिका 8-2: एंटाइटलमेंट मैट्रिक्स	35

चित्र विवरण

चित्र 1-1: डाकघर मशोबरा, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश की स्थिति	6
चित्र 1-2: अधिग्रहित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के फोटोग्राफ।	7
चित्र 2-1: अध्ययन पद्यति पोस्ट ऑफिस मशोबरा, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश के लिए भूमि अधिग्रहण में एसआईए आयोजित करने के लिए फलो चार्ट।.....	12
चित्र 2-2: मशोबरा, हिमाचल प्रदेश के स्थानीय क्षेत्र में समाचार पत्र और सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सार्वजनिक सुनवाई की जानकारी।	18
चित्र 2-3: मशोबरा, हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक सुनवाई की फोटोग्राफियाँ।	19

लघुरूप

बी एस ऑन एल	भारत संचार निगम लिमिटेड
सी पी आर	समुदायिक संपत्ति संसाधन
हि प्र	हिमाचल प्रदेश
पी ए एफ	परियोजना प्रभावित परिवार
पी ए पी	परियोजना प्रभावित व्यक्ति
हि प्र आर टी एफ सी टी एल ए आर	हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण और सहमति) नियम, 2015
आर एंड आर	पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन
एस आइ ए	सामाजिक समाघात निर्धारण
एस आइ एम पी	सामाजिक समाघात प्रबंध योजना
एस टी	अनुसूचित जनजाति

शब्दावली

- ❖ **अधिनियम** का अर्थ है: भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्या 30)।
- ❖ **प्रभावित क्षेत्र** का मतलब ऐसे क्षेत्र से है, जिन्हें भूमि अर्जन के उद्देश्यों के लिए उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।
- ❖ **प्रभावित परिवार में शामिल हैं:**
 - i. एक परिवार जिसकी भूमि या अन्य अचल संपत्ति का अर्जन किया गया है।
 - ii. ऐसा परिवार जिसके पास कोई जमीन नहीं है, लेकिन ऐसे परिवार के सदस्य (सदस्य) शायद खेतिहर मजदूर, किरायेदारों के किसी भी रूप में या उपभोग का अधिकार रखने वाले, कारीगरों के प्रति शेयर-फसल या जो प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे हों, तीन वर्ष, भूमि के अर्जन से पहले, जिसका आजीविका का प्राथमिक स्रोत भूमि के अर्जन से प्रभावित होता है।
 - iii. अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी जिन्होंने भूमि के अर्जन के कारण अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2 का 2007) के तहत मान्यता प्राप्त अपने किसी भी वन अधिकार को खो दिया है।
 - iv. परिवार जिसका अर्जन से पहले तीन वर्षों के लिए आजीविका का प्राथमिक स्रोत जंगलों या जल निकायों पर निर्भर है और इसमें वन उपज, शिकारी, मछुआरे और नाविक शामिल हैं और भूमि के अर्जन के कारण ऐसी आजीविका प्रभावित होती है।
 - v. परिवार का कोई सदस्य जिसे राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने अपनी किसी भी योजना के तहत जमीन सौंपी हो और ऐसी जमीन अर्जन के तहत हो।
 - vi. शहरी क्षेत्रों में किसी भी भूमि पर रहने वाले परिवार को भूमि के अर्जन से पहले तीन साल या उससे अधिक समय के लिए रहने की अनुमति या भूमि के अर्जन से पहले तीन साल तक आजीविका का प्राथमिक स्रोत ऐसी भूमि के अर्जन से प्रभावित होता है।
- ❖ **कृषि भूमि** का अर्थ है:
 - i. कृषि या बागवानी।
 - ii. डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, पिंसी कल्चर, सेरीकल्चर, सीड फार्मिंग, मवेशी प्रजनन या नर्सरी उगाने वाली औषधीय जड़ी-बूटियाँ।

- iii. फसलों, पेड़ों, घास या बगीचे की उपज का उत्पादन; तथा
- iv. पशुओं के चरने के लिए प्रयुक्त भूमि।

- ❖ **गरीबी रेखा से नीचे या BPL परिवार** भारत के योजना आयोग द्वारा परिभाषित गरीबी रेखा से नीचे गिरने वाले परिवारों को संदर्भित करता है, साथ ही समय-समय पर हिमाचल प्रदेश की **BPL** सूची में शामिल लोगों को भी शामिल करता है।
- ❖ **भूमि** में भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ शामिल हैं, और पृथ्वी से जुड़ी चीजें या स्थायी रूप से पृथ्वी से जुड़ी किसी भी चीज के लिए उपवास किया गया है।
- ❖ **भूमि अर्जन** का मतलब भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार के तहत भूमि का अर्जन है।
- ❖ **भूमिहीन** का अर्थ है ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जो हो सकते हैं:
लागू होने के समय के लिए किसी भी राज्य कानून के तहत माना या निर्दिष्ट; या भूमिहीन के एक मामले में खंड (i) के तहत निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता है, जैसा कि उपयुक्त सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- ❖ **भूमि स्वामी** में कोई भी व्यक्ति शामिल है-
 - (i) जिसका नाम दर्ज किया गया है वह संबंधित प्राधिकारी के रिकॉर्ड में भूमि या भवन का मालिक है या वहां का हिस्सा है; या
 - (ii) कोई भी व्यक्ति जिसे अनुसूचित अनुसूचित जनजाति पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 की अधिनियम संख्या 2) या किसी अन्य कानून के तहत वन अधिकार प्रदान किया जाता है; या
 - (iii) राज्य के किसी भी कानून के तहत भूमि पर पट्टा अधिकार दिए जाने का हकदार कौन है, जिसमें निर्दिष्ट भूमि या शामिल हैं
 - (iv) कोई भी व्यक्ति जिसे न्यायालय या प्राधिकरण के आदेश के अनुसार घोषित किया गया हो;
- ❖ **बाजार मूल्य** का अर्थ है धारा 26 क के अनुसार भूमि निर्धारण का मूल्य अधिनियम 2013।
- ❖ **अधिसूचना** का अर्थ है भारत के राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना या, जैसा कि मामला हो सकता है, एक राज्य का राजपत्र और अभिव्यक्ति "अधिसूचित" तदनुसार निर्धारित की जाएगी।

- ❖ **लोक प्रयोजन** का अर्थ है, धारा 2 एक्ट 2013 की उप-धारा (1) के तहत निर्दिष्ट गतिविधियाँ।
- ❖ **पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन (R & R)** का अर्थ है RFCTLARR अधिनियम 2013 के अनुसार पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन।
- ❖ **अनुसूचित क्षेत्र** का अर्थ अनुसूचित क्षेत्रों से है जैसा कि पंचायतों के प्रावधानों (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का 40) के प्रावधानों 2 में परिभाषित किया गया है।
- ❖ **छोटा किसान** छोटे कृषक का तात्पर्य ऐसे कृषक से है जिसके पास दो हेक्टेयर तक की असिंचित भूमि हो या एक हेक्टेयर तक की सिंचित भूमि हो, लेकिन सीमांत कृषक की जोत से अधिक हो।
- ❖ **सामाजिक समाघात निर्धारण** का मतलब अधिनियम की धारा 4 के उपधारा (1) के तहत किया गया मूल्यांकन है।
- ❖ **सामाजिक समाघात प्रबंध योजना** का अर्थ है अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया के भाग के रूप में तैयार की गई योजना।
- ❖ **राज्य सरकार या "सरकार"** का अर्थ है हिमाचल प्रदेश सरकार
- ❖ **किरायेदार** वे व्यक्ति होते हैं जिनके पास भूमि के अर्जन से पहले तीन साल के लिए बोनाफाइड टेनेंसी सम्झौते होते हैं, एक संपत्ति के मालिक के पास स्पष्ट संपत्ति खिताब के साथ, निवास, व्यवसाय या अन्य उद्देश्यों के लिए एक संरचना या भूमि पर कब्जा करने के लिए।
- ❖ **दुर्बल समूहों** में अलग-अलग लोगों जैसे कि एक, विधवा, और महिलाओं के नेतृत्व वाले घर, साठ साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य समूह शामिल हैं, जो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।
- ❖ **महिला प्रधान परिवार** का अर्थ है एक महिला की अध्यक्षता वाला परिवार और जिसमें कोई कमाने वाला पुरुष सदस्य नहीं है। यह महिला विधवा, परित्यक्त या परित्यक्त महिला हो सकती है।

कार्यकारी सार

परियोजना और लोक प्रयोजन

ग्राम मशोबरा, तहसील शिमला (ग्रामीण), जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में स्थित डाकघर भवन, मशोबरा के लिए भूमि अधिग्रहण के उद्देश्य से सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन।

प्रस्तावित भूमि, डाकघर मशोबरा के कार्यालय भवन के उद्देश्य से डाक विभाग, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित की जानी है। यह भूमि अधिग्रहण यह सुनिश्चित करेगा कि डाक विभाग के पास उनके भवन की भूमि का सुरक्षित और कानूनी स्वामित्व है जिस पर, समुदाय को विश्वसनीय डाक सेवाएं प्रदान करने और आधुनिक समाज के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में डाक प्रणाली के कामकाज का समर्थन करने के लिए डाकघर का निर्माण किया गया है। .

स्थान /अवस्थिति

प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण 387.56 वर्ग मीटर भूमि का कानूनी स्वामित्व प्राप्त करने के उद्देश्य से है, जिस पर डाकघर का भवन पहले से ही स्थित है। भूमि गांव मशोबरा, तहसील और जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में स्थित है।

भूमि अर्जन का आकार और विशेषता

मशोबरा, शिमला में डाकघर भवन के लिए 387.56 वर्ग मीटर की भूमि का प्रस्तावित अधिग्रहण, निजी भूमि के कई पारसल से बना है। भूमि की पहचान खसरा संख्या 1023,1056,1057,1058,1069,1060, 1061 किता-7 के रूप में की गई है, जो गांव मशोबरा, तहसील शिमला (ग्रामीण), जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भूमि शुरू में श्री चिंदू मल, के स्वामित्व में थी। बाद में इसे श्री भगत राम चौहान द्वारा खरीदा गया था।, जो अब अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के एकल शीर्षकधारक हैं।

अनुकल्पो पर विचार

जैसा कि डाक विभाग के पास 1973 से पहले से ही भूमि और भवन का कब्जा है, कार्यालय भवन को स्थानांतरित करने के लिए कोई अन्य व्यवहार्य विकल्प नहीं है। इसके अलावा, भूस्वामी ने शुरू में उचित मुआवजे के लिए डाक विभाग को भूमि सौंपने की इच्छा व्यक्त की थी, जिससे वैकल्पिक विकल्प तलाशना अनावश्यक हो गया था।

सामाजिक समाघात

मशोबरा में डाकघर के लिए भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण से समुदाय की आजीविका, रोजगार, आय, उत्पादन, स्वास्थ्य, कल्याण, सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवस्था और पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने की उम्मीद है।

सुगम अधिग्रहण प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, जमीन के मालिक और प्रभावित व्यक्तियों और समूहों सहित संबंधित हितधारकों से राय लेने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण के परिणाम अधिग्रहण के लिए मजबूत समर्थन दिखाते हैं, भूमि मालिक जमीन बेचने की इच्छा व्यक्त करते हैं और अन्य हितधारकों का मानना है कि यह समुदाय के सर्वोत्तम हित में होगा। सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर, सभी आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ अधिग्रहण प्रक्रिया एक कुशल और समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगी।

फोकस समूह चर्चा के दौरान, भूस्वामी ने प्रस्तावित अधिग्रहण के लिए उचित मुआवजे को स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त की। चूंकि भूमि केवल श्री भगत राम चौहान की है। सर्वेक्षण के दौरान, कोई संस्कृति या सामाजिक सामंजस्य, या कोई लिंग आधारित प्रभाव नहीं देखा गया।

शमन के उपाय

अध्ययन के दौरान पहचाना गया एकमात्र नकारात्मक प्रभाव भूस्वामी को भूमि का नुकसान था, जिसे दीर्घकालिक प्रभाव के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। हालांकि, अधिग्रहित की जा रही भूमि पर डाक भवन का निर्माण पहले ही हो चुका है, डाक विभाग के पास कई वर्षों से भूमि का कब्जा है, और प्रस्तावित अधिग्रहण के कारण कोई विस्थापन या आजीविका का नुकसान नहीं होगा।

हालांकि यह सच है कि भूमि से एक भावनात्मक मूल्य जुड़ा होता है, भूमि के नुकसान के लिए मालिक को पर्याप्त रूप से मुआवजा देकर प्रभाव को कम किया जा सकता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अध्ययन के दौरान किसी अन्य नकारात्मक प्रभाव की पहचान नहीं की गई है, और भूमि के अधिग्रहण का आजीविका, रोजगार, आय, उत्पादन, स्वास्थ्य, समुदाय, सामाजिक-सांस्कृतिक प्रणाली और पर्यावरण और जीवन की गुणवत्ता पर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सामाजिक लागत और फायदों का निर्धारण

हमारे प्राथमिक सर्वेक्षण और फोकस समूह चर्चाओं के दौरान, यह स्पष्ट हो गया कि परियोजना से प्रभावित परिवार पर कुछ नकारात्मक प्रभावों के बावजूद, परियोजना के सामाजिक लाभों ने व्यापक समुदाय के लिए सामाजिक लागतों को बहुत अधिक बढ़ा दिया। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम (आरटीएफसीटीएलएआरआर) 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार परियोजना प्रभावित परिवारों द्वारा अनुभव किए गए नुकसान और असुविधा के लिए पर्याप्त मुआवजा प्रदान करता है, जिसमें भूमि से जुड़ी संरचनाओं और संपत्तियों के लिए मुआवजा भी शामिल है। संक्षेप में, इस परियोजना का स्थानीय समुदाय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

1 विस्तृत परियोजना ब्यौरा

1.1 परियोजना की पृष्ठभूमि

डाक सेवा समकालीन समाज का एक अनिवार्य पहलू है, जो संचार, वाणिज्य और सामाजिक संपर्क के वैश्विक सूत्रधार के रूप में कार्य करती है। यह व्यक्तियों और व्यवसायों को लंबी दूरी पर पत्र, कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज़ भेजने की क्षमता प्रदान करता है, विशेष रूप से विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उन लोगों के लिए जहां इंटरनेट या अन्य संचार तकनीकों तक विश्वसनीय पहुंच सीमित हो सकती है। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माल और दस्तावेजों के शिपमेंट को सक्षम करने के लिए सेवा भी महत्वपूर्ण है, छोटे व्यवसायों को लाभान्वित करने के लिए जिनके पास अपने स्वयं के शिपिंग बुनियादी ढांचे को स्थापित करने के लिए संसाधनों की कमी हो सकती है। इसके अलावा, डाक सेवा लोगों को अपने प्रियजनों के साथ पत्र, कार्ड और अन्य वस्तुओं का आदान-प्रदान करने की अनुमति देकर सामाजिक संपर्क को सक्षम बनाती है, भले ही भौगोलिक रूप से अलग हो, जैसे लंबी दूरी के रिश्ते या सैन्य परिवार।

यह उल्लेखनीय है कि डाक सेवा को सार्वभौमिक सेवा प्रदान करने के लिए अनिवार्य किया गया है, जिसका अर्थ है कि यह सभी ग्राहकों की सेवा करती है, भले ही उनका स्थान या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। यह सुनिश्चित करता है कि सबसे दूरस्थ और कम सेवा वाले समुदायों की भी डाक सेवा के लाभों तक पहुंच हो।

डाक सेवा के महत्व का एक ऐसा उदाहरण मशोबरा डाकघर द्वारा दिया गया है, जो मशोबरा के मुख्य बाजार में स्थित है, जिसमें देवला, दुर्गापुर, घैनी, खटनोल, किरकोटी, पाहल और ठैला शाखा कार्यालय नाम से सात शाखा कार्यालय शामिल हैं। ये दोनों, शाखा कार्यालय और मशोबरा डाकघर मेल और पार्सल की डिलीवरी, वृद्धावस्था पेंशन, मनी ट्रांसफर, बैंकिंग, बीमा, खुदरा सेवाओं, कॉमन सर्विस सेंटर, आधार सेवाओं और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सेवाओं सहित कई प्रकार की डाक सेवाएं प्रदान करते हैं। ये सेवाएं लगभग 17 ग्राम पंचायतों के दरवाजे पर उपलब्ध कराई जाती हैं, जो लगभग 20,000 लोगों को सेवा प्रदान करती हैं जो अपनी संचार और बैंकिंग जरूरतों के लिए डाक सेवा पर निर्भर हैं।

डाक विभाग ने 1973 से मशोबरा में जमीन के एक भूखंड पर कब्जा बनाए रखा है, जिस पर मशोबरा डाकघर बनाने के लिए एक भवन का निर्माण किया गया था। भवन का निर्माण दो चरणों में किया गया था, प्रारंभिक चरण 1973 में शुरू हुआ था, और इसमें प्राथमिक भवन का निर्माण शामिल था, जो 31 जनवरी 1973 को पूरा हुआ था। दूसरा चरण, जो 1998 में शुरू हुआ, जिसमें सहायक संरचनाएं जैसे सीढ़ियां, रेलिंग और एक सेप्टिक टैंक का निर्माण 31 जुलाई 1999 को पूरा किया गया था।

पहले, विभाग को डाक और दूरसंचार विभाग के रूप में जाना जाता था, जिसे बाद में दो स्वतंत्र विभागों में विभाजित किया गया: डाक विभाग और दूरसंचार विभाग। वर्तमान में, दोनों विभाग, डाक विभाग और भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) दूरसंचार विभाग इस भवन का उपयोग करते हैं, और इसके एक हिस्से को बागवानी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार को भी किराए पर दिया गया है।

2002 में, भूमि के स्वामित्व को भूस्वामी श्री द्वारा चुनौती दी गई थी। भगत राम चौहान, जो स्वयं एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि थे (विधान सभा सदस्य, हिमाचल प्रदेश, 1990) श्री भगत राम चौहान इस मामले को अदालत में ले गए, अंततः भारत के सर्वोच्च न्यायालय में गए। सुप्रीम कोर्ट ने अंततः श्री भगत राम के पक्ष में फैसला सुनाया। परिणामस्वरूप, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के बाद, डाक विभाग वर्तमान में उस भूमि का अधिग्रहण करने की प्रक्रिया में है जिस पर भवन स्थित है।

1.1.1 अंतर राज्य / अंतर्राष्ट्रीय पहलू

ऐसा कोई अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय पहलू नहीं पाया गया है जो प्रस्तावित प्रक्रिया पर कोई प्रभाव डाल सके।

1.1.2 विकासक की पृष्ठभूमि

भारत में डाक प्रणाली का एक लंबा और आकर्षक इतिहास है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। भारत में डाक संचार का सबसे पहला प्रमाण मौर्य साम्राज्य (321-185 ईसा पूर्व) में देखा जा सकता है, जहां साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों के बीच संदेशों को ले जाने के लिए धावकों को नियुक्त किया गया था।

मुगल युग के दौरान, डाक प्रणाली को और विकसित किया गया था, और पूरे साम्राज्य में डाकघरों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया था। डाकियों को "डाक धावक" कहा जाता था और वे पैदल या घोड़े पर संदेश, पार्सल और आधिकारिक दस्तावेज ले जाते थे।

ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने 18वीं शताब्दी में भारत में अपना शासन स्थापित किया, ने डाक व्यवस्था के महत्व को पहचाना और इसे आधुनिक बनाने के लिए कदम उठाए। भारत में पहली नियमित डाक सेवा 1837 में शुरू की गई थी और पहला डाक टिकट 1854 में जारी किया गया था।

1858 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन ने भारत का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया, तो डाक व्यवस्था को सरकार के नियंत्रण में रख दिया गया। अगले कुछ दशकों में, डाक नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ, और 20वीं सदी की शुरुआत तक, भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी डाक प्रणालियों में से एक थी।

डाक प्रणाली ने स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और महात्मा गांधी सहित कई स्वतंत्रता सेनानियों ने एक दूसरे के साथ संवाद करने और अपना संदेश फैलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया।

1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद, डाक प्रणाली का आधुनिकीकरण किया गया और इसका और विस्तार किया गया, और स्पीड पोस्ट जैसी नई सेवाओं की शुरुआत की गई। आज, भारतीय डाक

प्रणाली 150,000 से अधिक डाकघरों और मेल वितरण, धन हस्तांतरण, ई-कॉमर्स वितरण और वित्तीय सेवाओं सहित सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ दुनिया में सबसे बड़ी है।

भारत में डाक विभाग, जिसे इंडिया पोस्ट के नाम से भी जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण संगठन है जो पूरे देश में डाक सेवाएं प्रदान करता है। यह 150,000 से अधिक डाकघरों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है, और देश भर में लोगों और व्यवसायों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है।

डाक विभाग की स्थापना 1854 में भारत में हुई थी और तब से, लोगों की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए इसमें कई परिवर्तन और आधुनिकीकरण हुए हैं। विभाग देश भर में लोगों, व्यवसायों और सरकारी संगठनों को जोड़ने में सहायक रहा है।

1.1.3 शासन या प्रबंधन संरचना

भारत में डाक विभाग संचार मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जो देश में डाक सेवाओं के विकास के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। विभाग का नेतृत्व महानिदेशक करते हैं, जिन्हें वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

डाक विभाग को 23 डाक मंडलों में बांटा गया है, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक मुख्य पोस्टमास्टर जनरल (सीपीएमजी) करता है। डाक हलकों को आगे क्षेत्रों, मंडलों और उप-प्रभागों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक स्तर का नेतृत्व एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया जा रहा है।

डाक विभाग के पास 400,000 से अधिक कर्मचारियों का कार्यबल है, जो देश भर में डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं। कर्मचारियों को विभिन्न संवर्गों में संगठित किया जाता है, जैसे डाक सहायक, छँटाई सहायक, डाकिया और अन्य, और उन्हें कुशल और विश्वसनीय डाक सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग, डाक विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार के समग्र प्रशासन और प्रबंधन ढांचे के तहत काम करता है। हालाँकि, राज्य स्तर पर, हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग का अपना शासन और प्रबंधन ढांचा है।

हिमाचल प्रदेश के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल राज्य में डाक सर्कल के प्रमुख हैं। सीपीएमजी के तहत, वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम होती है जो राज्य में डाक सेवाओं के दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होती है। टीम में डाकघरों के वरिष्ठ अधीक्षक (एसएसपीओ) और डाकघरों के अधीक्षक (एसपीओ) शामिल हैं, जो क्रमशः क्षेत्रीय और मंडल स्तर पर डाकघरों के कामकाज की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग को चार क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक का प्रमुख एक क्षेत्रीय पोस्टमास्टर जनरल (RPMG) होता है। क्षेत्रों को आगे डिवीजनल हेड या सब-डिवीजनल हेड के नेतृत्व में डिवीजनों और सब-डिवीजनों में विभाजित किया गया है।

स्थानीय स्तर पर, राज्य भर में 800 से अधिक डाकघर हैं, जिनका प्रबंधन पोस्टमास्टर और अन्य डाक अधिकारियों द्वारा किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग के कर्मचारियों को विभिन्न संवर्गों में संगठित किया जाता है, जैसे डाक सहायक, छंटनी सहायक, डाकिया और मल्टी-टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)। हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग राज्य के लोगों को कुशल और विश्वसनीय डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसने अपनी सेवाओं को आधुनिक बनाने और लोगों को अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए मोबाइल बैंकिंग, ई-कॉमर्स डिलीवरी और स्पीड पोस्ट जैसी कई नई पहलें शुरू की हैं। हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग राज्य के लोगों को एक दूसरे से और देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और राज्य के बुनियादी ढांचे का एक अनिवार्य हिस्सा है।

1.2 परियोजना औचित्य और सार्वजनिक उद्देश्य

मशोबरा डाकघर मशोबरा के मुख्य बाजार में स्थित है और इससे जुड़े 7 शाखा कार्यालय हैं, जो मेल और पार्सल की डिलीवरी, वृद्धावस्था पेंशन, धन हस्तांतरण, बैंकिंग, बीमा, खुदरा सेवा, सामान्य सेवा केंद्र, आधार सेवाएं और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सेवाएं सहित कई डाक सेवाएं प्रदान करते हैं। 17 ग्राम पंचायतों के लगभग 20,000 लोग घर-द्वार पर इन सेवाओं से लाभान्वित होते हैं। पोस्ट ऑफिस, मशोबरा और दुनिया के बाकी हिस्सों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है, खासकर उन लोगों के लिए जो दूर-दराज के इलाकों में रहते हैं और डिलीवरी सेवाओं तक सीमित पहुंच रखते हैं। डाक सेवाओं के अलावा, डाकघर बचत खातों, मनी ऑर्डर और बीमा पॉलिसियों जैसी वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है, जो उन लोगों के लिए आवश्यक हैं जिनकी पहुंच बैंकों या वित्तीय संस्थानों तक नहीं है।

हि प्र आर टी एफ सी टी एल ए आर अधिनियम, 2013 की धारा 2 उप-धारा -1b (v) के अनुसार डाकघर मशोबरा के लिए भूमि अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की परिभाषा के तहत उचित है।

इसलिए, हिमाचल प्रदेश भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापन (सामाजिक प्रभाव आकलन और सहमति) नियम, 2015 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भूमि के लिए एक सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन आयोजित किया गया है।

1.3 परियोजना विवरण

प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण उस भूमि का है, जिस पर डाक विभाग ने पहले से ही भवन का निर्माण कर लिया है तथा भूमि एवं भवन डाक विभाग के कब्जे में है, जिसके लिए वर्तमान एसआईए संचालित किया जा चुका है। नीचे दी गई तालिका परियोजना के विवरण को सारांशित करती है

तालिका 1-1: परियोजना का विवरण

1.	परियोजना का नाम	पोस्ट ऑफिस मशोबरा, तहसील और जिला मशोबरा हिमाचल प्रदेश
2.	अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल	387.56 वर्ग मीटर
3.	अवस्थिति	ग्राम मशोबरा, परगना शोहावली, तहसील और जिला शिमला हिमाचल प्रदेश
4.	क्षमता	लागू नहीं
5.	आउटपुट	लागू नहीं
6.	उत्पादन लक्ष्य	लागू नहीं
7.	लागत	लागू नहीं
8.	जोखिम	लागू नहीं

1.3.1 अवस्थिति

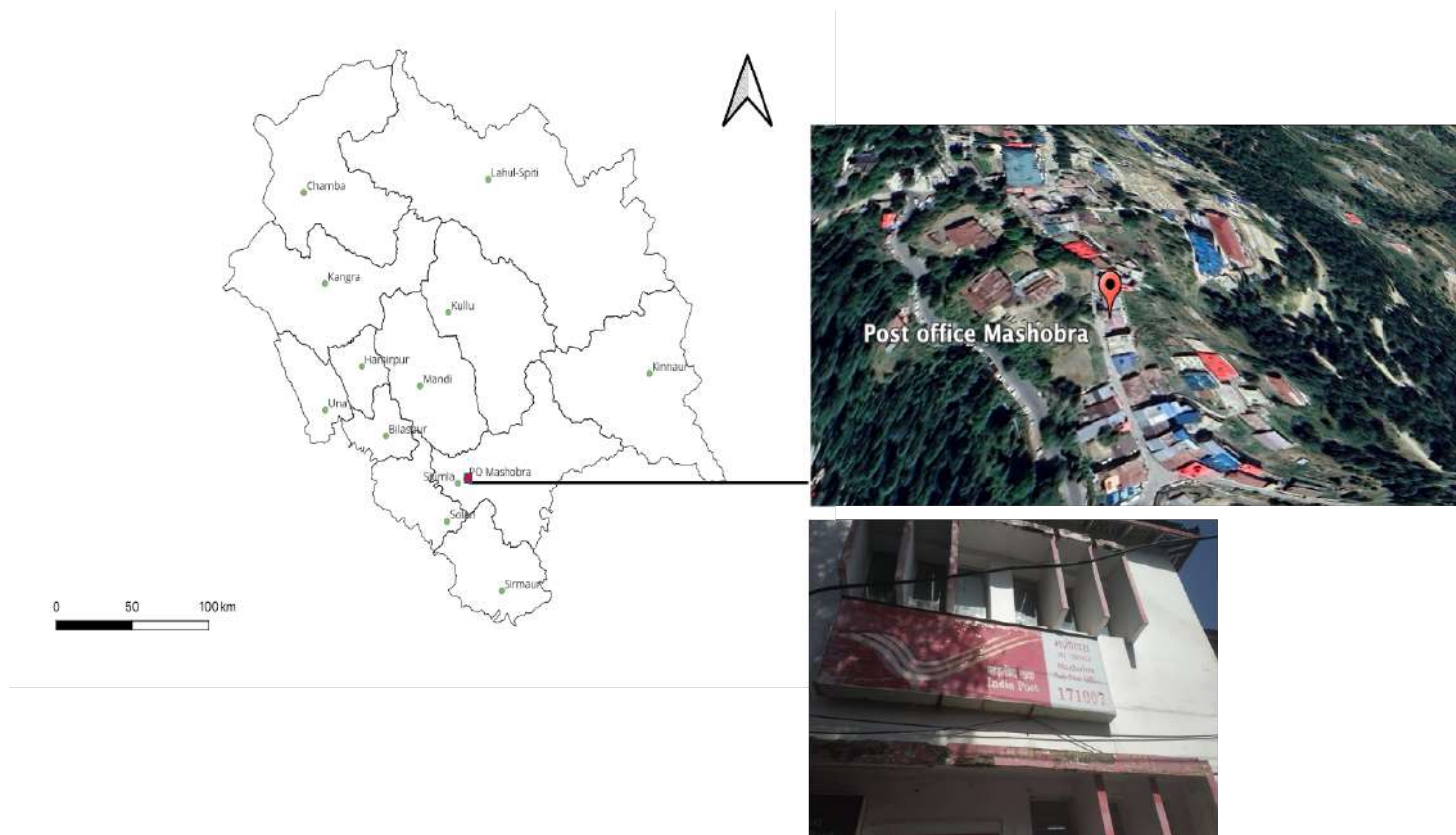
भूमि मशोबरा बाजार में स्थित है और हिमाचल प्रदेश के मशोबरा, परगना शोहावली, तहसील और जिला शिमला में खेत खतौनी नंबर 1023,1056,1057,1058,1069,1060, 1061 किता-7 के अंतर्गत आती है।

1.3.1.1 परियोजना क्षेत्र में पहुँच

प्रस्तावित स्थल शिमला बस स्टैंड से लगभग 16 किमी और चंडीगढ़ से लगभग 136 किमी दूर स्थित है। स्थान मुख्य बाजार मशोबरा है और राज्य राजमार्ग संख्या 13 से लिंक रोड पर स्थित है

अधिग्रहित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि मुख्य मुख्य बाजार मशोबरा में स्थित है। यह भूमि, 1973 से पहले से ही डाक विभाग के कब्जे में है और उक्त भूमि के टुकड़े पर भवन पहले से बना हुआ है, इसलिए विचार करने का कोई विकल्प नहीं है।

चित्र 1-1: डाकघर मशोबरा, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश की स्थिति



स्रोत : एस आइ ए टीम

चित्र 1-2: अधिग्रहित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के फोटोग्राफ।



स्रोत : एस आइ ए टीम

1.4 विकल्पों पर विचार

अधिग्रहण के लिए चिन्हित भूमि मशोबरा के मुख्य बाजार में स्थित है। यह 1973 से डाक विभाग के कब्जे में है, और भूमि पर एक भवन का निर्माण किया जा चुका है। इसलिए, कोई व्यवहार्य विकल्प मौजूद नहीं है जिसे विकल्प के रूप में माना जा सके।

1.5 परियोजना निर्माण के चरण

भवन का निर्माण पहले ही हो चुका है इसलिए परियोजना का चरणबद्ध रूप से विकास, लागू नहीं होता है।

1.6 मुख्य डिजाइन सुविधाएँ, आकार और सुविधाओं का प्रकार

भवन का निर्माण पहले ही किया जा चुका है इसलिए ऐसी कोई कोर डिजाइन, आकार और प्रकार की का विवरण नहीं हैं।

1.7 सहायक अवसंरचनात्मक सुविधाओं की आवश्यकता

इस परियोजना में उक्त आकलन लागू नहीं होता है

1.8 कार्यबल की आवश्यकता (अस्थायी और स्थायी)

इस परियोजना में उक्त आकलन लागू नहीं होता है

1.9 एसआईए या ईआईए का विवरण और अन्य तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट।

वर्तमान एसआईए को छोड़कर, जो 387.56 वर्ग मी निजी भूमि के वर्तमान अधिग्रहण के लिए आयोजित किया गया है, संबंधित एजेंसी द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है और साझा नहीं किया गया है।

1.10 लागू किये गए विधान और नीतियां

1.10.1 सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की तैयारी

हि प्र आर टी एफ सी टी एल ए आर अधिनियम, 2015 की धारा 4 में कहा गया है कि जब भी उपयुक्त सरकार किसी लोक प्रयोजनके लिए भूमि का अर्जन करने का इरादा रखती है, तो वह प्रभावित क्षेत्र में ग्राम स्तर या वार्ड स्तर पर संबंधित पंचायत से, उनके साथ, इस तरह से और ऐसी तारीख से जैसे कि सरकार द्वारा निर्दिष्ट अधिसूचना हो (अधिनियम की धारा 4) के तहत परामर्श करेगी और परामर्श में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करेगी।

हि प्र आर टी एफ सी टी एल ए आर नियम, 2015 के नियम 3 उपधारा (1) में कहा गया है कि राज्य सरकार अधिनियम के प्रयोजन के लिए, इनमें से फार्म -I के भाग-बी के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण करने के लिए एक अधिसूचना जारी करेगी। सामाजिक समाघात निर्धारण शुरू करने से संबंधित नियम हिंदी और अंग्रेजी दोनों संबंधित पंचायत या नगर पालिका या नगर निगम जैसा भी मामला हो सहित जिला कलेक्टर के संबंधित कार्यालयों में, उप-मंडलाधिकारी और तहसील को उपलब्ध कराए जाएंगे। कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन के माध्यम और प्रभावित क्षेत्रों में विशिष्ट स्थानों पर अधिसूचना चस्पाँ कर भी प्रभावित क्षेत्र में व्यापक प्रचार किया जाएगा, इसके अलावा, अधिसूचना राज्य सरकार की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी: (HP हि प्र आर टी एफ सी टी एल ए आर नियम, 2015)

2 दल संरचना, दृष्टिकोण, प्रणाली एवं सामाजिक समाघात निर्धारण की अनुसूची

यह अध्याय संक्षेप में टीम की संरचना और कार्यप्रणाली की समग्र संरचना का वर्णन करता है, जिसका उपयोग पोस्ट ऑफिस मशोबरा, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश के अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि के लिए SIA के संचालन के लिए किया गया है। निम्नलिखित खंड में जानकारी एकत्र करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों और विशिष्ट रणनीति के पीछे तर्क के विस्तृत विवरण पर चर्चा की गयी है।

2.1 दल विवरण

सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) टीम की संरचना तालिका 2.1 में दी गई है, जो इस एसआईए अध्ययन को करने के लिए जिम्मेदार थी। प्रत्येक टीम का सदस्य अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ है और उसने कई अध्ययन किए

तालिका 2-1: टीम विवरण

क्र.सं.	नाम	योग्यता	लिंग	विशेषज्ञता
1	ई. तरुण गुप्ता	बी.टेक (एजी), पीजी पीएम, पीजी डीएमएम	पुरुष	वरिष्ठ पर्यावरण अधिकारी, विभाग। पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी (सेवानिवृत्त) विशेषज्ञ ईआईए और एसआईए, रिपोर्ट लेख(टीम लीडर)
2	मंगत राम चौहान	एपीएमआईआर, पीजी मार्केटिंग मैनेजमेंट	पुरुष	प्रभाव आकलन और सामुदायिक संघटन (परियोजना समन्वयक)
3	रमन शर्मा	एम ए समाजशास्त्र, पीएच.डी.	पुरुष	सर्वेक्षण और डेटा विश्लेषण, प्रभाव आकलन और सामुदायिक जुटाव में विशेषज्ञ
	एम आर शर्मा	सामाजिक कार्य में स्नातक	पुरुष	सर्वेक्षण और सांख्यिकीय शोधकर्ता
5	संगीता	एम ए	महिला	सर्वेक्षण और सांख्यिकीय शोधकर्ता, और लिंग विशेषज्ञ
8	पूजा	एम काम	पुरुष	आई. टी विशेषज्ञ
9	निशिमा भारद्वाज	एम.ए. समाजशास्त्र	महिला	अन्वेषक और लिंग विशेषज्ञ

प्राथमिक सर्वेक्षण में भाग लेने वाले क्षेत्र सर्वेक्षणकर्ताओं की सूची निम्नलिखित है:

तालिका 2-2: सर्वेक्षकों की सूची

क्रमांक	नाम	योग्यता	लिंग	पद
1	पुष्प राज	एमएसडब्ल्यू	पुरुष	सर्वेक्षक
2	नितेश	एमए	पुरुष	सर्वेक्षक

2.2 प्रयुक्त पद्धति और उपकरण का विवरण व औचित्य

2.2.1 लक्ष्य

अध्ययन का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के अधिकार और भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्वास (सामाजिक समाघात निर्धारण और सहमति) नियमों, 2015 में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अनुसार एक सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना है।

2.2.2 उद्देश्य

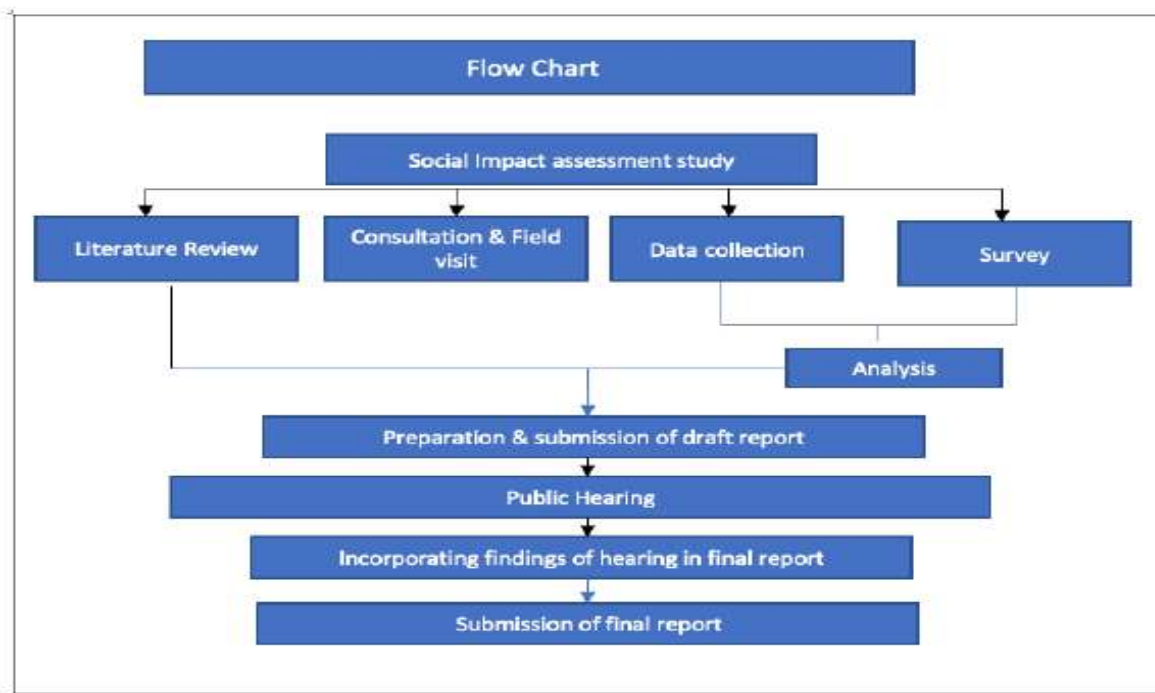
- 1 क्या प्रस्तावित अर्जन आरटीएफसीटीएलआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 2 के तहत सूचीबद्ध मानदंडों के अनुसार लोक प्रयोजनका कार्य करता है या नहीं, इसका आकलन करना।
- 2 प्रभावित परिवारों का अनुमान और उनके बीच विस्थापित होने की संभावना वाले परिवारों की संख्या का आकलन ।
- 3 प्रस्तावित अर्जन से भूमि, सार्वजनिक और निजी, घरों, बस्तियों और अन्य सामान्य संपत्तियों की प्रचुरता प्रभावित होने की संभावना का आकलन ।
- 4 क्या अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि की सीमा परियोजना के लिए आवश्यक न्यूनतम पूर्ण सीमा है।
- 5 क्या वैकल्पिक जगह पर भूमि अर्जन पर विचार किया गया है और संभव नहीं है।
- 6 परियोजना के सामाजिक प्रभावों का अध्ययन, और प्रकृति और उन्हें संबोधित करने की लागत और परियोजना के समय लागत पर इन लागतों के प्रभाव ने परियोजना के लाभों को देखा।

- 7 हि प्र आर टी एफ सी टी एल ए आर नियमों, 2015 के प्रपत्र 2 के अनुसार प्रभावित क्षेत्र और पुनर्वास स्थल की सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक प्रोफाइल तैयार करना (यदि कोई हो)।
- 8 हि प्र आर टी एफ सी टी एल ए आर नियमों, 2015 के प्रपत्र 3 के अनुसार एक सामाजिक समाघात प्रबंध योजना तैयार करना।

2.2.3 पद्धति

सामाजिक समाघात निर्धारण करने और एस आइ एम पी तैयार करने के लिए जो पद्धति अपनाई गयी , वह नीचे वर्णित है। एस आइ ए हि प्र आर टी एफ सी टी एल ए आर अधिनियम 2013 और हि प्र आर टी एफ सी टी एल ए आर नियम, 2015 के अनुसार तैयार किया गया । नीचे चित्र प्रवाह चार्ट के रूप में एस आइ ए अध्ययन के दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली को प्रस्तुत करता है।

चित्र 2-1: अध्ययन पद्धति पोस्ट ऑफिस मशोबरा, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश के लिए भूमि अधिग्रहण में एसआईए आयोजित करने के लिए फ्लो चार्ट।



*स्रोत : एसआईए दल

एसआईए अध्ययन करने और एसआईएमपी तैयार करने की प्रक्रिया/पद्धति।

1. साहित्य की समीक्षा

- ❖ उक्त प्रस्ताव से संबंधित न्यायालय का आदेश।
- ❖ अग्रवाल, एम (एन.डी.) भारत में कमजोर समूह - स्थिति, योजनाएं, भारत का संविधान।

2. परामर्श और क्षेत्र का दौरा

- ❖ हितधारकों की पहचान (प्राथमिक और माध्यमिक डेटा)
- ❖ फील्ड विजिट (साइट विजिट, पंचायत विजिट)
- ❖ हितधारकों के साथ परामर्श

3. आँकड़ों का संग्रहण

- ❖ माध्यमिक आँकड़े (पंचायत रिकॉर्ड, राजस्व विभाग)

4. प्राथमिक डेटा (प्रश्नावली और एफजीडी, क्षेत्र का दौरा) 100% नमूना सर्वेक्षण किया गया था और जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से तैयार प्रश्नावली का उपयोग किया गया था।

5. एकत्रित आँकड़ों का विश्लेषण

- ❖ विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों का गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण। एकत्र किए गए प्राथमिक और द्वितीयक डेटा का विश्लेषण
- ❖ एफजीडी से निकाला गया निष्कर्ष
- ❖ हितधारक परामर्श से निष्कर्ष निकाला गया
- ❖ साइट सर्वेक्षण से अवलोकन

6. मसौदा रिपोर्ट

2.2.4 पद्धति का औचित्य

सामाजिक समाघात अध्ययन एक समयबद्ध अध्ययन है और आगामी परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि पर आर्थिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से निर्भर लोगों के हित की चिंतन करता है। उपरोक्त कार्यप्रणाली को सामाजिक समाघात अध्ययन करने और सुनिश्चित करने के लिए अपनाया जाता है, संविधान के तहत स्थापित स्थानीय स्वशासन और ग्राम सभाओं के परामर्श से, डाकघर मशोबरा के लिए भूमि अर्जन के लिए एक मानवीय, भागीदारीपूर्ण, सूचित और पारदर्शी प्रक्रिया और प्रदान करना प्रभावित परिवारों के लिए उचित और उचित प्रतिकर जिनकी भूमि का अर्जन किया जाना प्रस्तावित किया गया है या इस अर्जन से प्रभावित हैं और ऐसे प्रभावित व्यक्तियों के लिए उनके पुनर्वास और पुनर्वास के लिए पर्याप्त प्रावधान करते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अर्जन का संचयी परिणाम होना चाहिए कि

प्रभावित व्यक्ति विकास में भागीदार बने अर्जन के बाद के अपने सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए अग्रणी हों।

2.2.4.1 सामाजिक प्रभाव अध्ययन के लिए परामर्श हेतु हितधारकों की पहचान

सभी प्रमुख हितधारकों की एक सूची तैयार की गई जो परियोजना से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगी। तब सूची को अंततः तीन व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया :

1. **प्राथमिक हितधारक:** इनमें अर्जित की जाने वाली भूमि के मालिक, उनके परिवार, जिनके नाम जमाबंदी पर दर्ज हैं और जो संपत्ति में अपनी भागीदारी का दावा करते हैं, जिनके पास अर्जित भूमि पर किसी भी प्रकार की आजीविका / निर्भरता है।।
2. **द्वितीयक हितधारक:** इनमें डाक विभाग, ग्राम पंचायत और क्षेत्र के स्थानीय निवासी शामिल थे। ये हितधारक सीधे अधिग्रहण से प्रभावित नहीं होंगे लेकिन परियोजना के कारण उन पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है।

हितधारकों की पहचान के बाद डेस्क समीक्षा की गई। आरटीएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 और एचपी आरटीएफसीटीएलएआरआर नियम, 2015, आर एंड आर नीति, राजस्व रिकॉर्ड, जिला जनगणना पुस्तिका, पंचायत रिकॉर्ड, न्यायालय के आदेश और सेवा क्षेत्रों जैसे दस्तावेज, जिसमें परियोजना क्षेत्र के लोग शामिल हैं, सरकारी और गैर-सरकारी स्रोतों से एकत्र किए गए थे। और समीक्षा की। ऐसे डेटा का संग्रह और समीक्षा मुख्य रूप से संबंधित क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता और सेवा वितरण प्रणाली के बारे में समझ विकसित करने के लिए थी।

2.3 सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए सूचना संग्रहण करने के लिए संसाधन

अध्ययन को अंजाम देने हेतु जानकारी प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्रोतों से एकत्र की गई थी।

1. **सूचना संग्रह उपकरण** - प्राथमिक हितधारकों और उन पर प्रभाव की तीव्रता के बारे में प्रामाणिक जानकारी एकत्र करने के लिए एक संरचित प्रश्नावली तैयार की गई थी। प्रश्नावली में गुणात्मक और मात्रात्मक जानकारी की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी।
2. **प्राथमिक सर्वेक्षण** - पूर्व-संरचित प्रश्नावली की सहायता से प्राथमिक हितधारकों का सर्वेक्षण किया गया। प्रश्नावली में शामिल पहलुओं में पीएएफ की पहचान विवरण, सामाजिक प्रोफाइल, पारिवारिक विवरण, व्यवसाय, आय का स्रोत, पारिवारिक व्यय, घरेलू संपत्ति, प्रभावित संरचना की जानकारी, वाणिज्यिक/स्वरोजगार गतिविधियों, रोजगार पैटर्न, राय और विचार शामिल थे। पीएएफ परियोजना और पुनर्वास और पुनर्वास पर। पीएएफ की राय और

विचारों को दर्शाने वाले प्रश्नों को छोड़कर प्रश्नावली का अधिकांश हिस्सा पूर्व-कोडित था, जिसे ओपन-एंडेड छोड़ दिया गया था और हितधारकों के साक्षात्कार के दौरान रिकॉर्ड किया गया था।

3. **एफजीडी** - अध्ययन का एक पहलू हितधारकों, जनप्रतिनिधियों और समुदाय के नेताओं के साथ परामर्श था। परामर्श ने हितधारकों और एसआईए टीम के बीच संचार की रेखा खोली और समुदाय द्वारा देखे गए प्रभावों की पहचान करने में मदद की। गांवों में उपलब्ध सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढांचे की स्थिति, अधिग्रहण के कारण किसी सामान्य संपत्ति के नुकसान, शिक्षा की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, रोजगार की स्थिति, निर्णय लेने में महिलाओं की भूमिका आदि के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए पंचायत स्तर पर विभिन्न हितधारकों के साथ एफजीडी आयोजित किए गए थे। विभिन्न हितधारकों द्वारा देखे गए सकारात्मक और नकारात्मक परियोजना प्रभावों सहित, सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाने और नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए उनके सुझाव।
4. **डेटा संग्रह और जमीनी सत्यापन का पर्यवेक्षण** - कोर टीम के सदस्यों ने डेटा संग्रह का पर्यवेक्षण किया, और सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के तहत आने वाले सौ प्रतिशत परिवारों के लिए जमीनी सत्यापन किया गया।

2.4 नमूनाकरण पद्धति

चूंकि पीएएफ की कुल संख्या केवल एक है, इसलिए एसआईए टीम ने श्री भगत राम चौहान व उनके बड़े बेटे के साथ बैठक की जो स्वयं एक अधिवक्ता हैं और उन्होंने जिला, उच्च और सर्वोच्च न्यायालय में मामले का अवलोकन किया है, जिसके तहत वर्तमान भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू की गई है।

2.5 सूचना अथवा डाटा स्रोतों के प्रयोग का पर्यवलोकन

एस आइ ए और एस आइ एम पी को, भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्स्थापन (सामाजिक समाघात निर्धारण और सहमति) नियम, 2015 में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार के फार्म-II के अनुसार फील्ड विजिट और स्टैकहोल्डर परामर्श के माध्यम से एकत्रित जानकारी, डेटा और आँकड़ों के आधार पर तैयार किया गया था, । नीचे आवश्यक डेटा एकत्र करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा स्रोतों का विवरण दिया गया है:

तालिका 2-3: सूचना और डेटा स्रोतों का अवलोकन

क्र स	सूचना	प्राथमिक स्रोत
1.	परियोजना क्षेत्र में जनसंख्या का जनसांख्यिकीय विवरण	परिवार सर्वेक्षण
	आयु, लिंग, जाति, धर्म	परिवार सर्वेक्षण
2.	गरीबी का स्तर	परिवार सर्वेक्षण/ समूह चर्चा
3.	कमजोर वर्ग	परिवार सर्वेक्षण
4.	परिवार में नातेदारी पैटर्न और महिलाओं की भूमिका	परिवार सर्वेक्षण
5.	सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन।	सभा
6.	सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन, प्रशासनिक, राजनीतिक और नागरिक समाज संगठन।	सभा
7.	भूमि उपयोग और आजीविका, कृषि और गैर कृषि और पशुधन	क्षेत्र/प्राथमिक सर्वेक्षण

*स्रोत: एस आइ ए दल

2.6 प्रमुख हितधारकों के साथ परामर्श और की गई लोक सुनवाई के संक्षिप्त विचरण की अनुसूची

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आयोजित जनसुनवाई का कार्यक्रम निम्नलिखित था।

तालिका 2-4: मशोबरा, हिमाचल प्रदेश में मुख्य संलग्नकों के साथ निर्धारित सार्वजनिक परामर्श तिथि

क्रमांक	ज़िला	तहसील	स्थान	जन सुनवायी की तिथि
1	शिमला	शिमला (ग्रामीण)	मशोबरा	17/5/2023

जन सुनवाई के दौरान समुदाय द्वारा दिए गए मुद्दे और सुझाव इस प्रकार हैं:

जनसुनवाई का आयोजन पंचायत समिति सभागार, बीडीओ कार्यालय परिसर मशोबरा में किया गया। सुनवाई की अध्यक्षता उप मंडलाधिकारी शिमला (ग्रामीण) ने की और कुछ अन्य लोगों के साथ पंचायती राज प्रतिनिधियों ने जन सुनवाई में भाग लिया।

प्रमुख निष्कर्ष :

- ❖ जन सुनवाई में उपस्थित लोगों द्वारा कोई मुद्दा नहीं उठाया गया। प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के लिए किसी व्यक्ति/संगठन ने आपत्ति नहीं की।
- ❖ अधियाची निकाय ने कहा कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भूमि मालिक को उचित मुआवजा प्रदान किया जाएगा।

चित्र 2-2: मशोबरा, हिमाचल प्रदेश के स्थानीय क्षेत्र में समाचार पत्र और सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सार्वजनिक सुनवाई की जानकारी।

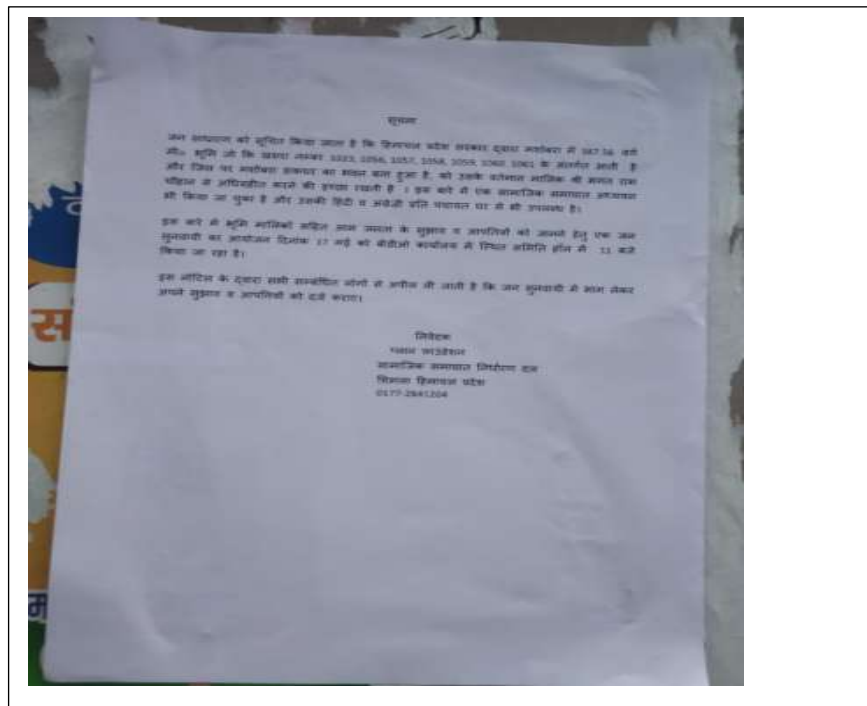
सूचना
डाकघर मशोबरा, जिला शिमला, (हि.प्र.) हेतु भूमि अर्जन बारे जन सुनवाई

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि डाकघर मशोबरा, जिला शिमला, हि.प्र. जो कि मशोबरा पंचायत में स्थित है, हेतु भूमि अर्जन किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु एक सामाजिक समाघात अध्ययन किया गया है जिसकी एक प्रति (हिन्दी व अंग्रेजी) सभी सम्बंधित पंचायत, तहसील, उपमंडल व जिलाधीश कार्यालयों में उपलब्ध है। इस बारे में पंचायत में जन सुनवाई का आयोजन निम्नानुसार किया जा रहा है। सभी प्रभावित परिवारों व पंचायत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि सम्बंधित तिथि को निम्नानुसार जन सुनवाई में भाग लें।

जिला	उपमंडल	पंचायत	प्रभावित गांव/मोहाल	जन सुनवाई का दिन व समय	जन सुनवाई का स्थान
शिमला	शिमला	मशोबरा	मशोबरा	17.05.2023 (1000-1100)	पंचायत घर मशोबरा

उक्त जन सुनवाई का नोटिस सम्बंधित कार्यालय उप मंडल समाहर्ता एवं उपमंडल अधिकारी द्वारा हिमाचल प्रदेश भूमि अधिग्रहण, पुनस्थापन और पुनर्वास में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के खंड 5 के अंतर्गत जारी किया जा चुका है जो कि सम्बंधित पंचायत, तहसील, उपमंडल व जिलाधीश कार्यालयों में उपलब्ध है।
अतः इस सूचना के द्वारा सभी को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विवरणानुसार जन सुनवाई में भाग लेकर अपने सुझाव व आपत्ति दर्ज कराएं।

निवेदक
सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल



*स्रोत: एस आइ ए दल

चित्र 2-3: मशोबरा, हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक सुनवाई की फ़ोटोग्राफियाँ।



*स्रोत: एस आइ ए दल

3 भूमि निर्धारण

यह अध्याय डाकघर भवन, मशोबरा, जिला के लिए अधिग्रहित की जाने वाली कुल निजी भूमि के विवरण पर केंद्रित है। प्राथमिक सर्वेक्षण सहित उपलब्ध नक्शे और प्राथमिक स्रोतों का उपयोग भूमि की प्रकृति, वर्तमान उपयोग और वर्गीकरण का पता लगाने के लिए किया गया है। पिछले तीन वर्षों के स्वामित्व पैटर्न, भूमि के हस्तांतरण और उपयोग पर एक संक्षिप्त विवरण का भी आकलन किया गया था।

3.1 भूमि तालिका की सूचना और प्राथमिक स्रोतों से जानकारी

कुल 387.56 वर्ग मीटर की निजी भूमि ग्राम मशोबरा, तहसील शिमला (ग्रामीण) जिला शिमला हिमाचल प्रदेश में खसरा नंबर 1023,1056,1057,1058,1069,1060, 1061 किता -7 में शामिल है।

प्रस्तावित भूमि एकल शीर्षक धारक श्री भगत राम चौहान की है। डाकघर भवन, जिसमें कर्मचारियों के आवास भी शामिल है, का निर्माण विभाग द्वारा किया गया है। यह जमीन 1973 से डाक विभाग के कब्जे में है।

तालिका 3-1: अधिग्रहण के तहत पीएएफ की भूमि

क्रमांक	भूमि मालिक	भूमि की मात्रा (वर्ग मी)
1	श्री भगत राम चौहान	387.56

3.2 परियोजना के प्रभाव में, प्रभाव का संपूर्ण क्षेत्र

प्रस्तावित अधिग्रहण के लिए 387.56 वर्ग मी कुल निजी भूमि की आवश्यकता है जो कि विभाग के कब्जे में है तथा उक्त भूमि पर भवन का निर्माण हो चुका है।

3.3 परियोजना के लिए कुल भूमि की आवश्यकता

अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित कुल निजी भूमि 387.56 वर्ग.मी. की आवश्यकता है। उक्त भूमि पर डाकघर की इमारत स्थित है, जो ग्राम मशोबरा, तहसील और जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में स्थित है।

3.4 क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में किसी भी सार्वजनिक, अनुपयोगी भूमि का वर्तमान उपयोग

प्राथमिक सर्वेक्षण और समूह केंद्रित चर्चा के दौरान, यह पाया गया कि क्षेत्र के आसपास कोई सार्वजनिक अनुपयोगी भूमि नहीं है। विभाग उक्त भूमि पर अपना भवन पहले ही बना चुका है, अतः अन्य भूमि के विकल्प की आवश्यकता नहीं है।

3.5 परियोजना के लिए आवश्यक भूमि के उपयोग हेतु प्रस्तावित पहले से ही खरीदी गई भूमि, अलग - अलग, लीज़ /अर्जित और प्रत्येक भूखंड के लिए प्रस्तावित उपयोग

अपेक्षक निकाय ने परियोजना के लिए न तो कोई भूमि खरीदी है और न ही लीज पर ली है। हालांकि, अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि का अभीष्ट उपयोग नीचे तालिका में प्रदान किया गया है:

तालिका 3-2: अधिग्रहित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि और उसका अभीष्ट उपयोग

क्रमांक	अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि	उपयोग का उद्देश्य
1.	खसरा नं. 1023 1056,1057,1058,1069, 1060,1061 किता -7	डाकघर का भवन, कर्मचारी आवास

3.6 परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि की मात्रा और स्थान

डाक विभाग के लिए अधिग्रहण की जाने वाली प्रस्तावित निजी भूमि मशोबरा, परगना शोहावली, तहसील और जिला शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित 387.56 वर्ग मी है।

3.7 भूमि का वर्तमान उपयोग प्रकृति, और वर्गीकरण

387.56 वर्ग मी की भूमि, जिस पर डाकघर का भवन स्थित है, ग्राम मशोबरा, तहसील और जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसे डाक विभाग के लिए अधिग्रहित किया जाना प्रस्तावित है।

तालिका 3-3: प्रस्तावित भूमि का वर्गीकरण

क्रमांक	भूमि मात्रा	प्रकार	उपयोग
1.	387.56 वर्ग मी	----	भवन

3.8 जोत / भूमी का आकार, स्वामित्व प्रकार

डाक विभाग के लिए अधिग्रहित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि शिमला जिला की पंचायत मशोबरा में आती है। परियोजना के लिए एकल/पारिवारिक भूमि/संपत्ति का अधिग्रहण किया जा रहा है।

3.9 भूमि वितरण एवं अधिग्रहीत किये जा रहे आवासीय भवनों की संख्या

एकल स्वामित्व धारक के स्वामित्व वाली 387.56 वर्ग मी भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव है। इस संपत्ति पर डाक विभाग द्वारा निर्मित डाकघर भवन स्थित है।

3.10 भूमि की कीमतें और हाल ही में स्वामित्व और हस्तांतरण में परिवर्तन

मुआवजे की गणना के लिए भूमि श्रेणी का वर्गीकरण निम्नानुसार दिया गया है:

1. श्रेणी-1 (0-25 मीटर): संपत्ति/भूमि जिसमें संबंधित खसरा संख्या या उसके भाग का कोई भी बिंदु सड़क से 25 मीटर की दूरी तक भूमि है।
2. श्रेणी-2 (20% <आधार दर) (25-50 मीटर): संपत्ति / भूमि जिसमें संबंधित खसरा संख्या या उसके हिस्से का कोई बिंदु ऐसी सड़क से 25 से 50 मीटर की दूरी पर नहीं है।
3. श्रेणी-3(40% < आधार दर)(50-100 मीटर): संपत्ति/भूमि जिसमें संबंधित खसरा संख्या या उसके भाग का कोई बिंदु ऐसी सड़क से 50 से 100 मीटर की दूरी पर नहीं है।
4. श्रेणी-4 (50% < आधार दर) (100-1000 मीटर): संपत्ति / भूमि जिसमें संबंधित खसरा संख्या या उसके हिस्से का कोई बिंदु ऐसी सड़क से 100 से 1000 मीटर की दूरी पर नहीं है।
5. श्रेणी-5 (60% <आधार दर)(>1000 मीटर): संपत्ति/भूमि जिसमें संबंधित खसरा संख्या या उसके भाग का कोई बिंदु ऐसी सड़क से 1000 मीटर या अधिक नहीं है।

एस आइ ए टीम को पिछले तीन वर्षों की अवधि में स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं मिला।

4 प्रभावित परिवारों और परिसंपत्तियों का प्राक्कलन और गणना

यह अध्याय डाक विभाग भवन के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों के आकलन एवं गणना पर केंद्रित है। इस अध्याय में इस भूमि अधिग्रहण के अन्तर्गत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों या व्यक्तियों, सामान्य संपत्ति, सार्वजनिक भूमि उपयोग निर्भरता का विवरण लिया जा रहा है। प्राथमिक सर्वे के जरिए यह जानकारी जुटाई गई है।

4.1 प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्ति

387.56 वर्ग मी निजी भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण का सीधा असर एकल परिवार पर पड़ रहा है। जमीन डाक विभाग के कब्जे में है। चूंकि मालिक वहां नहीं रहते थे, इसलिए इसमें कोई विस्थापन शामिल नहीं है।

4.1.1 किराएदार / कब्जाधारी

387.56 वर्ग मी निजी भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण का सीधा असर एकल परिवार पर पड़ रहा है। जमीन डाक विभाग के कब्जे में है। चूंकि मालिक वहां नहीं रहते थे, इसलिए इसमें कोई विस्थापन शामिल नहीं है।

4.1.2 जनजाति और पारंपरिक वन निवासी

कोई भी प्रभावित परिवार अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में नहीं आता है और न ही कोई पारंपरिक वनवासी है, जिसने अपना कोई वन अधिकार खोया है।

4.1.3 सामान्य संपत्ति संसाधनों पर निर्भरता

अधिग्रहित की जा रही भूमि पर कोई साझा संपत्ति संसाधन नहीं पाए गए

4.1.4 राज्य सरकार द्वारा दी गई भूमि

राज्य सरकार द्वारा अपनी किसी भी योजना के तहत कोई भी व्यक्ति भूमि आवंटित नहीं किया गया है और ऐसी भूमि अधिग्रहण के अधीन है

4.1.5 आजीविका के लिए भूमि पर निर्भरता

सर्वेक्षण के दौरान अधिग्रहित की जा रही भूमि पर कोई अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित पीएएफ या पीएपी नहीं पाए गए। भूमि पर कोई कृषि उपयोग संभव नहीं है क्योंकि डाकघर भवन उसी भूमि पर स्थित है।

4.2 अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित, उत्पादक संपत्तियों की सूची और महत्वपूर्ण भूमि

सर्वेक्षण के दौरान अधिग्रहित की जा रही भूमि पर कोई अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित पीएएफ या पीएपी नहीं पाए गए। भूमि पर कोई कृषि उपयोग संभव नहीं है क्योंकि डाकघर भवन उसी भूमि पर स्थित है।

5 सामाजिक- आर्थिक और सांस्कृतिक प्रोफाइल

अधिग्रहित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि एकल स्वामित्व धारक की निजी संपत्ति है और अधिग्रहण से प्राथमिक रूप से प्रभावित होने वाले व्यक्ति/परिवार इसके स्वामी होंगे। वर्तमान में परिसर में कोई भी व्यक्ति निवास नहीं कर रहा है और कोई भी व्यक्ति विचाराधीन भूमि से आजीविका की प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष निर्भरता प्राप्त नहीं कर रहा है। प्राथमिक हितधारक का विवरण निम्नानुसार है:

तालिका 5-1: प्राथमिक हितधारकों का विवरण

क्रमांक	नाम	गृह मुखिया से सम्बंध	आयु (वर्षों में)	लिंग	शैक्षणिक स्थिति	व्यवसाय
1.	भगत राम चौहान	मुखिया	85	पुरुष	एल एल बी	सेवा निवृत्त अधिवक्ता
2.	दिनेश चौहान	पुत्र	55	पुरुष	एल एल बी	अधिवक्ता
3.	महेन्द्र चौहान	पुत्र	52	पुरुष	स्नातक	बागवान/कृषि
4.	हितेंदर चौहान	पुत्र	48	पुरुष	स्नातक	व्यापार
5.	सुरेंद्र चौहान	पुत्र	43	पुरुष	स्नातक	व्यापार
6.	प्रेम चौहान	पुत्र	41	पुरुष	स्नातक	बागवान/कृषि

5.1 आय और गरीबी का स्तर

आय के स्तर के मामले में मालिक और परिवार अच्छा कर रहे हैं। श्री भगत राम चौहान हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विधायक थे। उन्होंने 1990 में भाजपा से चुनाव जीता। श्री। भगत राम चौहान स्वयं एक वकील रहे हैं और उनके एक पुत्र श्री दिनेश चौहान भी एक वकील हैं। परिवार "अविभाजित हिंदू परिवार" के अंतर्गत आता है और श्री भगत राम चौहान के सभी पुत्र अपने-अपने परिवार के साथ अलग-अलग जगह रह रहे हैं।

5.2 कमजोर समूह

सर्वेक्षण के दौरान पीएएफ के बीच कोई कमजोर समूह नहीं पाया गया।

5.3 भूमि उपयोग और आजीविका

राजस्व अभिलेखों के अनुसार अर्जित की जाने वाली भूमि का वर्गीकरण गैर कृषि है। इसके अलावा, सर्वेक्षण और क्षेत्र के दौरे के दौरान अधिग्रहित की जाने वाली भूमि पर किसी भी प्रकार की आजीविका निर्भरता (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से) नहीं पाई गई। अधिग्रहित की जा रही भूमि में और उसके आसपास स्थानीय आजीविका में योगदान करने वाली कोई स्थानीय आर्थिक गतिविधियां या कारक नहीं पाए जा सकते हैं जो परियोजना से प्रभावित होंगे

5.4 नातेदारी पैटर्न

हिमाचल प्रदेश में, भूमि अधिकार केवल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किए जाते हैं। राज्य के नियमों के अनुसार, कोई भी प्रवासी हिमाचल प्रदेश में जमीन नहीं खरीद सकता है। इसलिए, यहां की भूमि एक पैतृक संपत्ति है और यह केवल कानूनी उत्तराधिकारियों को समान रूप से वितरित की जाती है जब तक वसीयत अन्यथा न कहे।

महिलाएं पारिवारिक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और अधिकांश घरेलू कार्य महिलाओं द्वारा किए जाते हैं, जिसमें उनके द्वारा किए गए इन कार्यों का कोई आर्थिक मूल्यांकन नहीं किया जाता है।

5.5 प्रशासनिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और नागरिक समाज संगठन

अधिग्रहित की जा रही भूमि पर सिवाय डाकघर के भवन के कोई प्रशासनिक, राजनीतिक या नागरिक समाज संगठन नहीं पाया गया

5.6 क्षेत्रीय गतिशीलता और ऐतिहासिक परिवर्तन प्रक्रियाएं

अधिग्रहित की जाने वाली भूमि मशोबरा बाजार स्थित मात्र 387.56 वर्ग मी का एक छोटा सा टुकड़ा है। स्थान प्राथमिक है, क्योंकि यह क्षेत्र पर्यटन आकर्षण के लिए जाना जाता है और होटल, होम स्टे और अन्य संबंधित गतिविधियों की काफी संख्या क्षेत्र में स्थापित है। इसके अलावा, कोई भी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या धार्मिक स्थान नहीं मिला जो प्रभावित हो।

5.7 जीवंत पर्यावरण की गुणवत्ता

मशोबरा भारत के हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में स्थित एक सुरम्य स्थान है। यह समुद्र तल से 2,146 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और हरे-भरे जंगलों और बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है। यह

शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है, जो इसे एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाता है।

जीवन जीने के लिए अनुकूल पर्यावरण की गुणवत्ता के संदर्भ में, मशोबरा में ठंडी गर्मी और ठंडी सर्दियों के साथ एक सुखद जलवायु है। प्रदूषण के निम्न स्तर के साथ वायु की गुणवत्ता आम तौर पर अच्छी होती है, और पानी की गुणवत्ता को भी सुरक्षित और स्वच्छ माना जाता है। शहर ध्वनि प्रदूषण से अपेक्षाकृत मुक्त है, जो इसके शांतिपूर्ण वातावरण में जोड़ता है।

मशोबरा में अच्छी तरह से पक्की सड़कों, पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन और विश्वसनीय बिजली और पानी की आपूर्ति के साथ एक सुनियोजित और अच्छा बुनियादी ढांचा है। स्थान में अच्छी चिकित्सा सुविधाएं और शैक्षणिक संस्थान भी हैं, जो इसे परिवारों और बच्चों के रहने का एक उपयुक्त स्थान बनाते हैं।

कुल मिलाकर, मशोबरा अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांतिपूर्ण वातावरण और अच्छी तरह से विकसित बुनियादी ढांचे के साथ उच्च गुणवत्ता वाले रहने का वातावरण प्रदान करता है।

6 सामाजिक प्रभाव

यह अध्याय मशोबरा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में डाकघर के लिए भूमि अधिग्रहण के कारण सामाजिक प्रभावों के विस्तृत विश्लेषण पर चर्चा करता है। निम्नलिखित खंड जानकारी एकत्र करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों और इस परियोजना के प्रभाव के आकलन का वर्णन करते हैं।

6.1 प्रभावों की पहचान करने के लिए रूपरेखा और दृष्टिकोण

सामाजिक समाघात आकलन, दरअसल विकास, जैसे कि बांधों, खानों, उद्योगों, राजमार्गों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, शहरी विकास और बिजली परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं के नतीजों की संभावना का अग्रिम में, मूल्यांकन करना है। यह एक ऐसा उपकरण है जो निर्णयकर्ताओं को उनके कार्यों के संभावित नकारात्मक प्रभावों को दूर करने में मदद कर सकता है ताकि समय पर उन्हें रोकने या कम से कम किए जाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकें। निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायता के रूप में, एस आइ ए सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के बारे में जानकारी प्रदान करता है जिन्हें किसी भी निर्णय में ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है जो परियोजना क्षेत्र में लोगों के जीवन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है।

सामाजिक प्रभाव आकलन करने की प्रक्रिया को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिसमें प्रस्तावित अधिग्रहण के प्रभाव का आकलन करने के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण में सभी हितधारकों को शामिल किया गया है। प्रभावों की पहचान करने के लिए ढांचा और दृष्टिकोण निम्नलिखित चरणों में दिखाया गया है:

चरण 1: पृष्ठभूमि अध्ययन और केस अध्ययन

चरण 2: विभिन्न पी ए पी की पहचान

चरण 3: प्राथमिक सर्वेक्षण प्रश्नावली की तैयारी

चरण 4: विभिन्न हितधारकों के साथ प्राथमिक सर्वेक्षण और मुद्दा केंद्रित चर्चा का संचालन

चरण 5: एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण

6.2 परियोजना के विभिन्न चरणों में प्रभावों का विवरण

आम तौर पर भूमि के लिए सामाजिक प्रभावों को मोटे तौर पर 3 चरणों में वर्गीकृत किया जाता है, अर्थात्:

1. पूर्व निर्माण चरण के दौरान प्रभाव
2. निर्माण चरण के दौरान प्रभाव
3. कार्यान्वयन चरण के दौरान प्रभाव

हालांकि, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, चूंकि भवन का निर्माण अधिग्रहित की जा रही भूमि पर पहले ही किया जा चुका है, इसलिए निर्माण पूर्व और निर्माण चरणों के दौरान प्रभावों का अध्ययन नहीं

किया गया है। इसके अलावा, भूमि पहले से ही डाक विभाग के कब्जे में है, इसलिए समुदाय पर कोई नया प्रभाव नहीं पाया गया है। पीएपी को भूमिहीन होने का कोई खतरा नहीं है क्योंकि परिवार वहां नहीं रह रहा है। भूमि श्री भगत राम चौहान को विरासत में नहीं मिली है उन्होंने इसे दूसरे व्यक्ति से खरीदा था। परिवार उक्त भूमि से दूर गांव में रह रहा है।

7 अर्जन पर लागत और लाभ और सिफारिशों का विश्लेषण

यह अध्याय डाकघर मशोबरा, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश के लिए भूमि अधिग्रहण की लागत और लाभ विश्लेषण पर चर्चा करता है। अंत में, हितधारकों के साथ चर्चा के बाद, सिफारिशें प्रस्तुत की जाती हैं।

7.1 लोक प्रयोजन का आकलन

स्थानीय समुदाय में मशोबरा डाकघर के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है। कई मायनों में, यह मशोबरा के लोगों को बाकी दुनिया से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करता है। डाकघर द्वारा पत्रों, पैकेजों और पार्सलों का शीघ्र वितरण सुनिश्चित किया जाता है, जो विशेष रूप से दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वालों के लिए महत्वपूर्ण है, जहां अन्य वितरण सेवाएं संचालित नहीं हो सकती हैं। इसके अलावा, डाकघर बचत खाते, मनी ऑर्डर और बीमा पॉलिसी सहित कई वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। ये सेवाएं उन व्यक्तियों के लिए अपरिहार्य हैं जिनकी बैंकों या आसपास के अन्य वित्तीय संस्थानों तक पहुंच नहीं है।

कुल मिलाकर, मशोबरा डाकघर एक महत्वपूर्ण संस्थान है जो स्थानीय समुदाय को अमूल्य सेवाएं प्रदान करता है। यह लोगों को दुनिया से जोड़ने, वित्तीय सेवाओं की पेशकश करने, रोजगार के अवसर पैदा करने और सामुदायिक केंद्र के रूप में कार्य करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

यह महत्वपूर्ण बात है कि हिमाचल प्रदेश, शिमला जिले के माशोबरा डाकघर के लिए भूमि अधिग्रहण, 2013 के धारा 2 (1) के उप-धारा (बी) (ई) के अनुसार सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की परिभाषा के तहत उचित है।

7.2 न्यूनतम विस्थापन विकल्प और न्यूनतम भूमि की आवश्यकता

भारत में डाकघरों के निर्माण जैसे सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि का अधिग्रहण एक आम बात है। हालांकि, किसी भी अधिग्रहण प्रक्रिया को शुरू करने से पहले कम विस्थापन वाले विकल्पों और न्यूनतम भूमि की आवश्यकता का पता लगाना आवश्यक है।

इस संदर्भ में डाकघर भवन के लिए मशोबरा, शिमला में 387.56 वर्ग मी भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण से स्थानीय समुदाय और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव की चिंता नहीं है। उक्त भूमि पर डाक विभाग द्वारा एक भवन का निर्माण किया जा चुका है तथा भूमि एवं भवन लंबे समय से डाक विभाग के कब्जे में है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में, भूमि अधिग्रहण और भूमि के मालिक को मुआवजा प्रदान करने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है।

अंत में, जबकि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि का अधिग्रहण आवश्यक हो सकता है, स्थायी विकास सुनिश्चित करने और स्थानीय समुदायों और पर्यावरण पर प्रभाव को कम करने के लिए कम विस्थापन वाले विकल्पों और न्यूनतम भूमि की आवश्यकता पर विचार करना महत्वपूर्ण है। जमीन पहले से ही डाक विभाग के पास है और मामला केवल मुआवजे का है, इसलिए अब तक कम विस्थापन के विकल्प और न्यूनतम जमीन की आवश्यकता का सवाल है।

प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के कारण लोगों को किसी तरह के विस्थापन का सामना नहीं करना पड़ेगा। भूमिधारक अपनी भूमि इस शर्त के साथ समर्पित करने को तैयार है कि उसे उचित पर्याप्त मुआवजा दिया जाए।

इसलिए यह स्पष्ट है कि अधिग्रहित की जा रही भूमि डाक विभाग के लिए समुदाय की सेवा करने और डाकघर भवन के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले सार्वजनिक धन की रक्षा के लिए आवश्यक न्यूनतम और आवश्यक भूमि है। इसके अलावा, कोई उपयुक्त वैकल्पिक भूमि / सरकार नहीं। डाकघर के निर्माण के लिए आसपास जमीन उपलब्ध थी। साथ ही इस अधिग्रहण से कोई विस्थापन भी नहीं हो रहा है।

7.3 सामाजिक प्रभावों की प्रकृति और तीव्रता

एक प्रभाव, यदि प्रकृति में स्थायी है, निर्माण के बाद के चरण के दौरान पूर्व-निर्माण / निर्माण चरण के दौरान समान तीव्रता वाला होगा, दूसरी ओर अस्थायी प्रभाव परियोजना चक्र के निम्नलिखित चरणों के दौरान तीव्रता में निरंतर कमी दिखाएगा। निर्माण चरण के बाद भी कोई भी प्रभाव दीर्घकालिक प्रभाव के रूप में माना जाता है और यदि यह केवल निर्माण चरण चल रहा है, तो इसे अल्पकालिक प्रभाव माना जाता है।

अध्ययन द्वारा सुझाए गए शमन उपायों पर सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एसआईएमपी) के तहत विवरण में चर्चा की गई है। प्रभावित परिवारों की राय और मांगों के आधार पर और परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए, परियोजना के सकारात्मक और साथ ही कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। इस परियोजना का राज्य के साथ-साथ राष्ट्र पर भी निश्चित सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

परियोजना का एकमात्र नकारात्मक प्रभाव शीर्षकधारकों को भूमि और घर का नुकसान है जिसकी क्षतिपूर्ति का प्रस्ताव है। भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण के कारण कोई विस्थापन नहीं होगा।

7.3.1 अंतिम सिफारिश

उपरोक्त विश्लेषण से, यह स्पष्ट है कि डाक सेवा राज्य द्वारा आम लोगों को प्रदान की जाने वाली महत्वपूर्ण आवश्यक सेवाओं में से एक है। जमीन पहले से ही डाक विभाग के कब्जे में है और उसी जमीन पर विभाग द्वारा भवन का निर्माण भी किया जा चुका है। विभाग ने पूर्व में भूमि अधिग्रहण का दावा किया था जिसे माननीय न्यायालय ने नहीं स्वीकारा था। डाक विभाग वर्तमान अधिग्रहण प्रक्रिया के

माध्यम से भूमि के एक टुकड़े पर स्वामित्व अधिकार प्राप्त करेगा। इसका मतलब यह हो सकता है कि विभाग के पास विवादित भूमि का उपयोग करने, कब्जा करने और नियंत्रित करने का कानूनी अधिकार होगा, जिस पर पहले किसी और का स्वामित्व हो सकता था। अध्ययन में सिफारिश की गई है कि डाक विभाग के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण किया जाना चाहिए, बशर्ते कि पहचान किए गए विभिन्न प्रभावों को कम करने के लिए सुझाए गए सभी उपायों का न्यायिक रूप से पालन किया जाए।

8 सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना

यह सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एसआईएमपी) आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 और एचपी आरटीएफसीटीएलएआरआर नियम, 2015 के अनुसार नकारात्मक सामाजिक प्रभावों को कम करने और परियोजना के सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार की गई है।

8.1 शमन के लिए दृष्टिकोण

यह सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एसआईएमपी) आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 और एचपी आरटीएफसीटीएलएआरआर नियम, 2015 के बाद तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य नकारात्मक सामाजिक प्रभावों को कम करना और प्रस्तावित अधिग्रहण के सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाना है। इसमें प्रतिकूल सामाजिक प्रभावों को खत्म करने या उन्हें स्वीकार्य स्तर तक कम करने के लिए परियोजना के डिजाइन, निर्माण और परिचालन चरणों के दौरान शमन, निगरानी और संस्थागत उपायों का एक सेट शामिल है। एसआईएमपी परियोजना के विभिन्न चरणों के दौरान लागू किया जा सकता है, जैसे, पूर्व-निर्माण, निर्माण और परिचालन चरण।

वर्तमान अधिग्रहण प्रक्रिया में अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि डाक विभाग के कब्जे में है, जिस पर उन्होंने काफी पहले डाकघर का भवन बना दिया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 और एचपी आरटीएफसीटीएलएआरआर नियम, 2015 के तहत भूमि अधिग्रहण की यह प्रक्रिया शुरू की गई है।

8.2 समाघात से बचाव, कम करने और प्रतिपूर्ति करने के उपाय

यदि हितधारकों के बीच कोई विवाद है, तो पहले इस विवाद को सुलझाया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कानूनी मालिक को मुआवजा दिया जाए।

8.3 आर एंड आर में शामिल उपाय और अधिनियम 2013 के अनुरूप मुआवज़ा

यह एसआईएमपी रिपोर्ट आवश्यक निकाय के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करने और सार्वजनिक परामर्श और सर्वेक्षण के दौरान परियोजना प्रभावित परिवारों और अन्य हितधारकों द्वारा व्यक्त की गई आकांक्षा के अनुसार कार्य योजना तैयार करने के लिए फायदेमंद होगी। अध्ययन के निष्कर्षों के आलोक में अपेक्षित सामाजिक प्रभावों को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं।

तालिका 8-1: पहचाने गए और संबंधित शमन उपाय

क्र० सं	प्रभाव	सुझाव/ शमन उपाय
1	निजी भूमि का नुकसान (387.56 वर्ग मी)	हि प्र आर टी एफ सी टी एल ए आर अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार शीर्षक धारकों और हितधारकों को उचित प्रतिकर
2	निजी संपत्तियों के नुकसान के कारण अर्जन जैसे आवासीय और वाणिज्यिक संरचनाएं, सीमा की दीवारें, फसलें, फल असर और गैर-फल वाले पेड़। प्राप्त की जा रही निजी संपत्तियों की सूची तालिका 4.2 और 4.3 में उल्लिखित है	उक्त प्रावधान को लागू करने की स्थिति नहीं है
3	विस्थापित परिवारों और व्यक्तियों के लिए अर्जन के कारण असुविधा	उक्त प्रावधान को लागू करने की स्थिति नहीं है
4	भूमि पर निर्भर रोजगार / आय / आजीविका का नुकसान।	उक्त प्रावधान को लागू करने की स्थिति नहीं है
5	सामुदायिक संपत्ति जैसे घराट, शमशान घाट, बावड़ी, नदी पार करने वाले रोपवे, मंदिर आदि की हानि	उक्त प्रावधान को लागू करने की स्थिति नहीं है
6	पेयजल संसाधनों जैसे झरनों/बावड़ियों सहित जल संसाधनों जैसी सामान्य संपत्तियों की हानि। जलाऊ लकड़ी के संग्रह के लिए चारागाहों/चराई भूमि, जंगलों का नुकसान।	उक्त प्रावधान को लागू करने की स्थिति नहीं है
7	खाद्य सुरक्षा और पशुपालन पर प्रभाव: खेती योग्य भूमि और चरागाह के नुकसान से कृषि और पशुपालन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।	उक्त प्रावधान को लागू करने की स्थिति नहीं है
8	शोर प्रदूषण और वाहनों का आवागमन	उक्त प्रावधान को लागू करने की स्थिति नहीं है
9	वायु प्रदूषण	उक्त प्रावधान को लागू करने की स्थिति नहीं है

*स्रोत: एस आइ ए टीम

8.3.1 एसआईएमपी कार्यान्वयन के लिए परिव्यय

परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए लागू कानूनी प्रावधानों की पृष्ठभूमि में पात्रता ढांचा और पुनर्वास और पुनर्स्थापन की प्रक्रिया नीचे प्रस्तुत की गई है।

भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों, नियमों और नीतियों के अनुपालन में एक एंटाइटेल्मेंट मैट्रिक्स विकसित किया गया है। एंटाइटेल्मेंट मैट्रिक्स घाटे के प्रकार और संबंधित प्रकृति और एंटाइटेल्मेंट के दायरे को सारांशित करता है।

तालिका 8-2: एंटाइटेल्मेंट मैट्रिक्स

क्र.सं.	प्रभाव श्रेणी	हक की इकाई	पात्रता का विवरण	टिप्पणी
भू मालिकों के परिसम्पत्ती का नुकसान-				
	निजी भूमि	भूमि मालिक / शीर्षकधारी	<p>बाजार मूल्य पर भूमि के) लिए नकदप्रतिकर, जिसे आर टी एफ सी टी एल ए आर अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा</p> <p>खोए हुए परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन के लिए प्रतिकर की राशि पर वर्तमान स्टांप शुल्क के बराबर राशि।</p> <p>बारहमासी और गैर-बारहमासी फसलों और पेड़ों के नुकसान की भरपाई बागवानी और कृषि विभाग के लागू होने वाले प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।</p> <p>पशु शेड या छोटी दुकानों के प्रतिस्थापन के लिए 25,000 रुपये का अनुदान।</p>	<p>भूमि के मुआवजे में भूमि से जुड़ी सभी संपत्तियों का मुआवजा शामिल है।</p> <p>उक्त प्रावधान को लागू करने की स्थिति नहीं है</p> <p>उक्त प्रावधान को लागू करने की स्थिति नहीं है</p>

क्र.सं.	प्रभाव श्रेणी	हक की इकाई	पात्रता का विवरण	टिप्पणी
	संरचना का नुकसान आवासीय या) वाणिज्यिक या आवासीय-सह- (वाणिज्यिक	भूमि मालिक / शीर्षकधारी	<p>अ) स्वीकार्य मानदंडों के अनुसार वर्तमान दरों के आधार पर निर्धारित नकद प्रतिकर</p> <p>ब) हटाए गए परिवारों के लिए आर टी एफ सी टी एल ए आर अधिनियम, 2013 की प्रावधानिकताओं के अनुसार 50,000 रुपये का स्थानांतरण भत्ता।</p> <p>(सी) आर टी एफ सी टी एल ए आर अधिनियम, 2013 के अनुसार पूरी तरह से हटाए गए आवासीय / वाणिज्यिक या बनाए गए घर के स्थान पर मुफ्त घर की प्रावधानिकता या निर्मित घर के बराबर लागत प्रस्तावित की जा सकती है</p> <p>(डी) हटाए गए परिवारों के लिए जीविकोपार्जन भत्ता, जिसकी राशि 36,000 रुपये है (आर टी एफ सी टी एल ए आर अधिनियम, 2013)</p> <p>(ई) हटाए गए परिवारों के लिए पुनर्वास भत्ता, जिसकी राशि 50,000 रुपये है (आर टी एफ सी टी एल ए आर अधिनियम, 2013)</p>	उक्त प्रावधान को लागू करने की स्थिति नहीं है
	किरायेदारों और पट्टे धारकों	किरायेदारों और पट्टे धारकों	पंजीकृत पट्टियां लागू स्थानीय कानूनों के अनुसार संरचना के मालिक को देय प्रतिकर के एक	उक्त प्रावधान को लागू करने की स्थिति नहीं है

क्र.सं.	प्रभाव श्रेणी	हक की इकाई	पात्रता का विवरण	टिप्पणी
			परिशोधन के लिए हकदार होंगी।	
आवासीय और वाणिज्यिक संरचनाओं का नुकसान गैर-शीर्षकधारक -				
	कब्जा करने वालों के	प्रभावित व्यक्ति (व्यक्ति/ परिवार)	(ए) अतिक्रमणकारियों को संपत्ति / फसलों को हटाने के लिए 2 महीने का आग्रही सूचना दी जाएगी। (ब) प्रभावित संरचना से सामग्री को बचाने का अधिकार।	उक्त प्रावधान को लागू करने की स्थिति नहीं है
आजीविका की हानि शीर्षक और गैर-शीर्षकधारक -				
	आजीविका का नुकसान - शीर्षक धारक, कृषि श्रम और वाणिज्यिक बोली	(व्यक्ति/ परिवार)	एक बार का अनुदान 25,000 रु (मान के तहत निर्धारित आर टी एफ सी टी एल ए आर अधिनियम 2013)	उक्त प्रावधान को लागू करने की स्थिति नहीं है
	निर्माण के चरण के दौरान संभावित और अप्रत्याशित प्रभाव की संभावना है	स्वामी, प्रभावित व्यक्ति	(ए) यदि कोई हो तो , संरचना के नुकसान का भुगतान किया जाएगा। (ब) जहां आवश्यक हो, अस्थायी पहुंच प्रदान की जाएगी।	उक्त प्रावधान को लागू करने की स्थिति नहीं है
	मोबाइल कियोस्क की आय का अस्थायी नुकसान, यदि कोई हो	कियोस्क मालिक	दो महीने का अग्रिम नोटिस क्षेत्र खाली करें	
	SC, ST		सरकारी मानदंड योजनाओं में शामिल करने के लिए सहायता यदि शामिल नहीं है, तो सरकारी मानदंडों के अनुसार	

क्र.सं.	प्रभाव श्रेणी	हक की इकाई	पात्रता का विवरण	टिप्पणी
			पात्र; और आर टी एफ सी टी एल ए आर अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार एससी और एसटी को अतिरिक्त लाभ अनुसूची	
	प्रभावहीन प्रभाव		किसी भी अप्रत्याशित प्रभाव को अधिनियम के सिद्धांतों और उद्देश्यों के अनुसार प्रलेखित और कम किया जाएगा।	

पुनर्वास और पुनर्वास की लागत का विवरण तैयार नहीं किया गया है, हालांकि परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए लागू कानूनी प्रावधानों की पृष्ठभूमि में पात्रता ढांचे और पुनर्वास और पुनर्वास की प्रक्रिया को पहले प्रस्तुत किया गया है।

8.4 आवश्यक निकाय द्वारा सुझाए गए उपाय

चूंकि अधिग्रहित की जा रही भूमि के कारण कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, इसलिए अपेक्षक निकाय द्वारा कोई आर एंड आर उपाय नहीं बताया गया है।

8.5 अपेक्षित निकाय द्वारा सुझाए गए अतिरिक्त उपाय

अपेक्षित निकाय द्वारा कोई अतिरिक्त उपाय साझा नहीं किया गया है

8.6 पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत व्यवस्था

अधिनियम 2013 के अनुसार, जहां अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि 100 एकड़ के बराबर या उससे अधिक है, सरकार एक "पुनर्वास और पुनर्स्थापन समिति" का गठन करेगी। चूंकि प्रस्तावित अधिग्रहण केवल 387.56 वर्ग मी के लिए है, इसलिए यह लागू नहीं हो सकता है।

9 निष्कर्ष और सिफारिश

यह अध्याय एसआईए टीम के प्राथमिक सर्वेक्षण, हितधारक परामर्श और क्षेत्रीय दौरों के आधार पर एक निष्कर्ष और सिफारिशें प्रदान करता है। निष्कर्ष प्रत्येक उद्देश्य के तहत प्रस्तुत किए जाते हैं, उसके बाद सिफारिशें दी जाती हैं।

उद्देश्य, अवलोकन/निष्कर्ष और सिफारिशें

उद्देश्य:-

1. मूल्यांकन कि क्या प्रस्तावित अधिग्रहण आरटीएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 2 के तहत सूचीबद्ध मानदंडों के अनुसार सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा करता है।
 - प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में भूमि के अधिग्रहण के लिए शुरू की गई है जो पहले से ही लंबे समय से डाक विभाग के कब्जे में है और उस पर डाकघर भवन का निर्माण किया गया है मशोबरा और आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए आवश्यक डाक सेवाएं और प्रदान किया जा रही है। ।
 - स्थानीय समुदाय के लिए आवश्यक डाक सेवाओं को जारी रखने के लिए FGDs और मालिक और माध्यमिक हितधारकों के साथ परामर्श के दौरान वर्तमान भूमि अधिग्रहण का समर्थन किया। इसलिए, भूमि अधिग्रहण प्राधिकरण भूमि मालिक के मुद्दों को विधिवत संबोधित करते हुए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ सकता है।
2. प्रभावित परिवारों का अनुमान और उनमें से विस्थापित होने वाले परिवारों की संख्या।
 - 387.56 वर्ग मी निजी भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण से एक हकधारी को इस हद तक प्रभावित किया जा रहा है कि वह लंबे समय से डाक विभाग के कब्जे वाली जमीन का मालिक है और डाक विभाग लंबे समय से स्थानीय समुदाय को आवश्यक डाक सेवाएं प्रदान कर रहा है । मालिक उक्त भूमि पर न तो रहता है और न ही कोई संचालन करता है और यह भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के

निर्देशों के अनुपालन में शुरू की गई है। कुल प्रस्तावित भूमि का अधिग्रहण एक स्वत्वाधिकारी से किया जाना है।

- प्रस्तावित अधिग्रहण से कोई भी व्यक्ति भूमिहीन नहीं होने वाला है।

3. प्रस्तावित अधिग्रहण से प्रभावित होने वाली भूमि, सार्वजनिक और निजी, घरों, बस्तियों और अन्य सामान्य संपत्तियों की सीमा।

- प्रस्तावित अधिग्रहण 387.56 वर्ग मी निजी भूमि का है जो लंबे समय से डाक विभाग के कब्जे में है और उस पर डाकघर भवन का निर्माण किया गया है और मशोबरा और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को आवश्यक डाक सेवाएं प्रदान कर रहा है।

4. क्या अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि की सीमा परियोजना के लिए आवश्यक न्यूनतम सीमा में है।

- प्रस्तावित अधिग्रहण 387.56 वर्ग मी निजी भूमि का है जो लंबे समय से डाक विभाग के कब्जे में है और उस पर डाकघर भवन का निर्माण किया गया है और मशोबरा और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को आवश्यक डाक सेवाएं प्रदान कर रहा है।
- यह भूमि अधिग्रहण के लिए एकमात्र उपलब्ध विकल्प है क्योंकि भूमि पहले से ही लंबे समय से डाक विभाग के कब्जे में है और मशोबरा और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को आवश्यक डाक सेवाएं प्रदान कर रही है।

5. क्या वैकल्पिक स्थान पर भूमि अधिग्रहण पर विचार किया गया है और इसे व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

- जैसा कि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि लंबे समय से डाक विभाग के कब्जे में है और विभाग ने उस पर डाकघर भवन का निर्माण किया है और मशोबरा और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को वैकल्पिक स्थान के मुद्दे के रूप में आवश्यक डाक सेवाएं प्रदान कर रहा है अतः विचार नहीं किया गया।

6. परियोजना के सामाजिक प्रभावों का अध्ययन, और उन्हें संबोधित करने की प्रकृति और लागत और परियोजना की समग्र लागत पर परियोजना के लाभों के साथ-साथ इन लागतों का प्रभाव।

- प्रस्तावित भूमि का अधिग्रहण भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में है जो पहले से ही लंबे समय से डाक विभाग के कब्जे में है और विभाग ने उस पर डाकघर भवन का निर्माण किया है और आवश्यक डाक सेवाएं प्रदान कर रहा है
7. एचपीआरटीएफसीटीएलएआरआर नियम, 2015 के फॉर्म-II के अनुसार प्रभावित क्षेत्र और पुनर्वास स्थल (यदि कोई हो) की सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक रूपरेखा तैयार करना।
- रिपोर्ट के अध्याय 5 में रखे गए एचपीआरटीएफसीटीएलएआरआर नियम, 2015 के फॉर्म-II के अनुसार प्रभावित क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक प्रोफाइल तैयार किया गया है।
8. एचपीआरटीएफसीटीएलएआरआर नियम, 2015 के फॉर्म III के अनुसार सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना तैयार करना।
- एचपीआरटीएफसीटीएलएआरआर नियम, 2015 के फॉर्म III के अनुसार सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना तैयार किया गया है और रिपोर्ट के अध्याय 8 में रखा गया है।

अनुशंसाएँ:-

प्रस्तावित भूमि का अधिग्रहण भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में है जो पहले से ही लंबे समय से डाक विभाग के कब्जे में है और विभाग ने उस पर डाकघर भवन का निर्माण किया है और लोगों को आवश्यक डाक सेवाएं प्रदान कर रहा है। मालिक भी इस भूमि को प्रदान करने के लिए तैयार है बशर्ते उचित मुआवजा और उसके द्वारा उठाए गए मुद्दों और मुद्दों को सकारात्मक रूप से संबोधित किया जाए और समय पर और वैध तरीके से हल किया जाए।

10 संदर्भ

1. एस आइ ए अधिसूचना
2. भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार।
3. हिमाचल प्रदेश भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक प्रभाव आकलन और सहमति) नियम, 2015
4. सम्बंधित भूमि का न्यायालय आदेश